हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

2 मार्च, 1979

खण्ड 1 अंक–3

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भाुक्रवार 2 मार्च, 1979

पृश्ठ संख्या

तरांकित प्र न एवं उत्तर	(3) 1
सदस्य को निकालना	(3) 24

तंराकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(3) 25
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(3) 26
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(3) 31
वि ोशाधिकार भंग का प्र न	(3) 40
वाक–आउट	(3) 43
ध्यानाकर्शण सूचना	(3) 44
19–2–79 को बहादुरगढ़ उपमंडल के गांवों मे तुफान से खडी फसलों के नश्ट होने सम्बन्धी	
सदस्य को निकालना	(3) 45
ध्यानाकर्शण सूचना(पुनरारम्भ)	(3) 45
वित्त मंत्री का ध्यानाकर्शण सूचना के बारे में वक्तव्य	(3) 46
राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा	(3) 47

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार 2 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक , हरियाणा सभा हाल , विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः साहिबान, अब सवाल होगें।

तारांकित प्र न सं0 948

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योकि माननीय सदस्य, सरदार तारा सिंह, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

H.C.S. posts filled up through Haryana Public Service Commission.

***968. Shri Jai Narain Verma:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of H.C.S. posts filled up through Haryana Public Service Commission since 1-11-1966 to-date;

(b) the number of posts exclusively reserved for persons belonging to the Backward Classes;

(c) whether it is a fact that no candidate belonging to the Backward Classes has been appointed to H.C.S. cadre through direct recruitment.

(d) if the reply to part (c) be in the negative] the number of such persons appointed as H.C.S.; and

(e) if the reply of part (c) be in affirmative the reasons therefore?

उद्योग मंत्री (डा0 मंगल सैन): एच0सी0एच0 (कार्यकारी भााखा) तथा एच0सी0एस0 (न्यायिक भााखा) के बारे में अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है–

एच0सी0एस0 (कार्यकारी भााखा)

(क) 46

(ख) 13–9–78 तक 2 प्रति ात तथा 14–9–78 से 5 प्रति ात

(ग) नहीं ।

(घ) 1

(ड) उपर 'घी' पर दी गई सूचना के दृश्टिगत इस भाग के उत्तर की आव यकता नहीं।

एस0सी0एस0 (न्यायिक भााखा)

(क) 57

(ख) 13–9–78 तक 2 प्रति ात तथा 14–9–78 से 5प्रति ात

(ग) हां।

(घ) उपर 'ग' पर दी गई सूचना के दृश्टिगत इस भाग के उत्तर की आव यकता नहीं।

(ड) एच0सी0एस0 (न्यायिक भााखा) में सब जजिज की भर्ती के लिये हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा समय समय पर परीक्षायें ली जाती रही है। इन परीक्षाओं में अभी तक पिछडें वर्ग का कोई उम्मीदवार सफल नहीं हो पया है।। 1978 मे ली गई परीक्षा का परिणाम अभी प्रतीक्षित है।

श्री जय नारायण वर्मा: स्पीकर साहब, मैने अपने सवाल में नम्बर आफ पोस्टस का आरक्षण पूछा था लेकिन इन्होने परसैंटेज बताई है?

श्री अध्यक्ष: आपके सवाल का जवाब आ गया है। इन्होने पहले 2प्रति ात और उसके बाद 5 प्रति ात रिजर्वे ान के बारे मैं बताया है।

श्री जय नारायण वर्मा: अभी जो एच0सी0एस0 के एग्जाम हुये थे उसमें 5 प्रति ात का आरक्षण था। क्या उस 5 प्रति ात आरक्षण की पालना हुई है?

डाक्टर मंगल सैन: मैने जवाब में यह कहा है कि 14–9–78 के बाद सरकार ने यह तय किया है पिछडी जातियों के लोगों को 5 प्रति ात आरक्षण दिया जायेगा और उसके अनुसार अमल किया गया है।

चौधरी पीरचन्द: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सन 1970 के सन 1978 तक कितने लोग एच0सी0एस0 जुडि ियल में लिये गये ओर उनमें से हरिजन कितने लिये होगें?

डाक्टर मंगल सेन: स्पीकर साहब, यह सवाल बैकवर्ड क्लासिज के बारे में पूछा गया है। हरिजनों के बारे में मैंबर साहब अलग से नोटिस दे दें, जवाब दे दिया जाएगा।

Civil Hospital at Palwal

***977. Shri Mool Chand Mangla:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to raise the strength of beds from 30 to 100 in the Civil Hospital being constructed at Palwal. and

(b) if so, the time by which the proposal is likely to be materialized?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डा0 कमला वर्मा):

(क) जी नहीं।

(ख) प्र न नहीं उठता।

श्री मूल चन्द मंगला: मंत्री महोदया ने अपने जवाब में कहा है कि 'नहीं'। मैं मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि पलवल इतना बडा भाहर है वहां पर कम से कम सौ बैडज का हस्पताल होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: यह तो आपका सुझाव है, आप सवाल पूछिये।

श्री मूलचन्द मंगला: स्पीकर साहब ,वहां की आबादी करीब एक लाख है ओर मंत्री महोदया के जवाब से मेरी तसल्ली नहीं हुई है, इसलिये मै पूछना चाहता हूं कि वहां पर सौ बैडज का हस्पताल क्यों नही बनाया जा सकता?

श्रीमती डा0 कमला वर्मा: पहले हस्पताल वहां पर बनाये जाऐगें जहां पर मैडिकल एंड बिल्कुल भी नहीं है। पलवल में हम 30 बैडज का हस्पताल बना रहे है ओर 30 बैडज का हस्पताल बनाने की वजह से वहां पर एक और डाक्टर इनको मिल जायेगा। फंडज की अवेलेबिलिटी होने पर आगे सौचा जा सकता है। जो अब 30 बैडज का हस्पताल बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा

कि आगे उस पर 4–5 लाख रूपये ओर लगा कर उसके बैडज बढाये ं जा सकेगें।

चौधरी ई वर सिंहः मंत्री महोदया ने बताया है कि पलवल मे 25 बैडज के हस्पताल की बजाये 30 बैडज का बना रहे है। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां पर हस्पताल बिल्कुल ही नहीं है वहां पर खोलने का क्या क्राइटेरिया है? अब कहां–कहां खोले जा रहे है?

श्रीमती डा0कमला वर्माः क्राइटेरिया जनसंख्या के आधार पर और लोागो की जरूरत के आधार पर तय किया जाता है। अगले पाचं साला प्लान के अन्दर यह सोचा गयाहै कि जहां बहुत अधिक आव यकता होगी वहां पर हस्पताल जरूर खोले जायेगें इस वक्त 30 बैडज के हस्पताल चुटाला, सोहना, जगाधरी और पलवल में खोले जा रहे है।

श्री देवेन्द्र भार्माः मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो हस्पताल चुटाला में खोला जा रहा है वह इसलिये तो नहीं खोला जा रहा कि वह चीफ मिनिसटर साहब का गांव है?

श्रीमती डा0 कमला वर्माः यह बिलकुल गलत बात है। वहां पर इसलिये खोला जा रहा है कि चुटाला के आ पास बहुत गांव है जहां मैडिकल एड बिलकुल भी नही है।

श्री भागी रामः सिरसा जिले में एलनाबाद की आबादी 50 हजार हैं क्या मंत्री महोदया ने वहां पर बडा हस्पताल खोलना जरूरी नहीं समझा?

श्रीमती डा0 कमला वर्माः जरूरी तो हमसब जगह समझते है लेकिन अपने बजट को देखते हुये जो हस्पताल अपग्रेड किये जा सकेगके उनको जरूर किया जायेगा।

कामरेड भंाकरलाल : मैं मंत्री महोदया से पूछनार चाहता हूमं कि चूकि सिरसा डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है इसलिये क्या वहां पर पुराने हस्पताल की बजाये नया हस्पताल खोला जायगा?

श्रीमती डा0 कमला वर्माः अगले साल के लिये यह विचारधीन है।

चौधरी संत कंवरः मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हं कि जिस गांव के चारो तरफ 15 किलोमीटर के एरिया मे कोई हस्पताल नहीं है अगर उस गांव की पंचायत खुद बिल्डिंग बना कर दे दे तो क्या वहां पर हस्पताल खोल दिया जायेगा?

श्रीमती डा0 कमला वर्माः वहां पर अव य खोल दिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः यानि अगर कोई गांव पैसा देने के लिये तैया हो तो वहां पर हस्पताल जरूर खोल दिया जायेगा, यह आपकी अ योरेंस है।

श्रीमती डा0 कमला वर्माः ब ार्ते कि वहां पर हस्पताल खोलने की जरूरत हो।

चौधरी भाग मलः सढौरा के हस्पताल की कंडी ान बहुत खराब है क्या गवर्नमेंट उसके लिये नई बिल्डिंग बनाने की सोच रही है या नहीं?

श्रीमती डा0 कमला वर्माः 1979–80 में यह विचाराधीन है।

कंवर राम पाल सिंहः मन्त्री महोदया ने अभी बताया कि जहां जहां पर आव यकता होगी वहां वहां पर हस्पताल खोले जायेगें। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नया हस्पताल खोलने के लिये क्या क्या चीजें कसिंडर करते है?

श्रीमती डा0 कमला वर्माः जिस गांव की जनसंख्या अधिक हो ओर आस पास मैडिकल एड की सूविधा न हो, ऐसे गांवों में हस्पताल खोलने का विचार किया जाता है। जो गांव मेन रोड पर हैं वहां के लोग तो आसानी से भाहर में जा सकते है। लेकिन जो गांव इन्टीरियर में है, उनको फर्स्ट प्रेफॅरेंस दिया जाता है।

चौधरी राम कि ानः यहां पर यह कहा गया था कि दो साल में हर क्षेत्र में एक–एक डिस्पैंसरी खोल दी जायगी लेकिन दो साल बीत चुके है। कोई भी डिसंपैंसरी नहीं खोली गई है, इसका क्या कारण है?

श्रीमती डा0 कमला वर्मा: यह सवाल पलवल के बारे मे पूछा गया थ, सारे हरियाणा के बारे मे नहीं

श्री अध्यक्ष : आप अलग से नोटिस देदे बता देगें।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, जिन मंत्रियों के पास यह महकता रहता है, वे जब किसी गांव मैं जाकर वहां के लोागें की जरूरतो को समझते है तो हस्पताल खोलने की अनाउसमेंट कर देते है लेकिन वहां फिर भी कोइ हस्सपताल नहीं खोला जाता। क्या उस कमिटमेंट के अनुसार वहां हस्पताल खोले जायेगें, अगर हां तो कब तक खोले जायेगें?

श्रीमती डा0 कमला वर्मा: हम कमिटमेंटस को एग्जामिन करवा रहे है और जहां जहां मिनिस्टरों ने अस्पताल खोलनरे के लिये कमिटमेंटस की है वहां पर फण्डज को ध्यान में रखते हुये अस्पताल खोलने की कोि ा ा करेगें (विधन)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय ने अ योंरेस दे दी है कि जिस जगह पर मिनिस्टर्ज अनाउंसमेंट करके आये है वहां पर जरूर हस्पताल खोलने की कोि ा ा करेगें।

Allotment of plots at Panchkula

***991. Master Shiv Parshad:** Will the Minsiter for agriculture by pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to allot residential plots at Panchkula to those persons who deposited earnest money in March, 1972 for the allotment of 10 marla plots, if

so, the names of sector where the plots are likely to be allotted to them?

कृशि मंत्री (ब्रिगेंडियर रण सिंह): असल में हालत यह है कि हमारे पास मार्च 1972 में 6 हजार 8 सौ ऐप्लीकें ांज थी लेकिन 78 तक जमीन के भाव बढ गये थे ओर जो ऐप्लीकेटंस थे हमने उनको और रूपया जमा करनो के लिये कहा। उनमें से तीन हजार नौ सौ आदमियों ने रूपया जमा करपा दिया था। इनमं से 1700 आदतियां को हम प्लाट दे चुके है। 22 सौ एप्लीकैंटस अभी बाकी है। 22 सौ मे से 15 सौ को दो चार महीनों में प्लाटस सैक्टर 13–14 में दे दिये जायेगें। इस तरह सात सौ ऐप्लीकैंटस बच जायेगें।

मास्टर ि ाव प्रसादः इस अलाटमेंट का क्या क्राइटेरिया बनाया गया है?

बिग्रेडियर रण सिंहः मेरा ख्याल था कि आनरेबल मैंबर्ज को इतना मालूम होना चाहिये कि जितनी ऐप्लीके ांज हमारे पास डयू डेट तक आती है उनको हम प्लाट अलाट करने के लिये ड्रा निकालते है। इस ड्रा में जिसका नम्बर आ जाता हैं उनको प्लाट दे देते है।

श्री फतेह चन्द विजः कब से ये एप्लीके न्ज पैंडिग पडी है,, स्पीकर साहब, 72–73 के बाद वालो को तो प्लाट दे दिये गये है लेकिन 1972–73 वालों को अभ तक प्लाट नहीं दिये गये है इसका क्या कारण है?

बिग्रेडियर रण सिंहः सिर्फ उन आदमियों को प्लाट दिये गये है जिनका ड्रा में नम्बर आया हैं जो बाकी बचे है उनमें से 15 सौ को द ो चार महीने में प्लाट दे दिये जायगें।

श्री लहरी सिंह मेहराः यह जो प्लाटों की आलटमेंट की जाती है क्या इसमें हरिजनो के लिये रिजर्वे ान रखी जाती है।

श्री अध्यक्षः यह तो प्लाट देने की बात है, नौकरी देने की बात नही है।

श्री जय नारायण वर्माः मैं तो मन्त्री महोदय को हिन्दी में जवाब देने की बधाई देता हूं।

चौधरी संत कंवरः मैं मन्त्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं क्योंकि ये किसान के बेटे है। क्या इन्होने अलाटमेंट की यह जो व्यवस्था की है, इसमें जिन किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी, उनके लिये कोर्ठ प्लाट रखे गये है?

ब्रिगेडियर रण सिंहः असल बात यह है कि यहां हम सब प्लाट अलाट से देते है लेकिन यह सवाल जो मेरे भाई उठाया है। उसके बारे में विचार कर रहे है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी इस बारे में कुछ बातें कहीहै। हम समझते है कि जिन किसान भाइयों की जमीन एक्वायर की गई है, उनको भी कुछ न कुछ मिलना चाहिये। सबसे पहले तो हम उसको एक प्लाट देगें जिसकी जमीन हम लेते है लेकिन मुख्य मंत्री महोदय जी ओर मेने इस पर और

विचार किया हैं हम उनको इससे भी ज्यादा सुविधायें देना चाहते ह।

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, लहरी सिंह जी ने अभी पूछा था कि क्या हरिजनों के लिये इस आलटमेंट में कोई रिजर्वे ान की गई है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आयां। सैंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हरिजन और स्वर्ण जातियों के लोग मिक्स होकर रहें। इसलिये हरियाणा सरकार को भी चाहिये कि प्लाटों की आलाटमेंट में यह भी रिजर्वे ान रखे ताकि हरिजन और दूसरे भाई इक्टठे रह सकें।

ब्रिगेडियर रण सिंहः इसके लिये आप हरिजन भाइयों को कहे कि वे प्लाटों के लिये अप्लाई करे।

Amendment in qualifications for the recruitment to H.E.S. Class I

***992. Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Minister for Education be pleased to State-

(a) the reasons for which the recent amendment in qualifications for the direct recruitment of H.E.S. Class I has been made in which M.Ed. (Master of Education) degree has been down graded and equated with B.T/B.Ed./SAV/O.T./D.T.; and

(b) the reasons for which M.Ed. has been replaced by M.Com. in the essential qualifications for the direct recruitment to H.E.S. Class I?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरानन्द):

(ए) अभी तक ऐसा कोई सं ाोधन नहीं हुआ है। अतः इसके लिये कोई कारण बताने का प्र न उत्पन्न नहीं होता।

(बी) प्र न उत्पन्न नहीं हेाता।

डा0 बृज मोहन गुप्ता: क्या इसका सुझाव हरियाणा सरकार ने पब्लिक सर्विस कमी ान को भेजा है कि एम0एड. को बी0एड0 और बी0टी0 के बराबर कर दिया जाये और एम0एड0 की बजाये एम0काम0 कर दिया जाये?

श्री हीरा नन्द आर्य: जहां तक एम0एड0 का संबंध है, एम0एड. एम0ए0 के बराबर नहीं माना जा सकता और न ही एम0एड0, बी0एड0 के बराबर माना जा सकता है। कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी एम0एड0 को बी0एड0 के बराबर नहीं माना है।

डा0 बृज मोहन गुप्ता: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब सीलोन यूनिवर्सिटी ने एम0एड0 को एम0ए0 के बराबर माना है और दूसरी यूनिवर्सिटीयों ने भी उसको फालो किया है तो मंत्री महोदय क्यों नहीं एम0एड0 को एम0ए0 के बराबर मानते?

श्री हीरा नन्द आर्य: एम0एड0, बी0एड0 के बाद एक साल का कोर्स है। इसलिये इसके बराबर करने का सवाल पैदा नहीं होतां।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब 'बी' पार्ट के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा है कि सवाल पैदा नहीं होता। मै। उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई सुझाव देकर उसको विदड्रा किया गया है या नही? (विघ्न) यह जवाब ठीक तरह से नहीं दे रहे है।

Mr. Speaker: The minister is quite capable of answering any question.

श्री हीरा नन्द आर्य: जब कोंई अमैंडमेंट का सवाल ही नहीं है तो ओर नई बात क्या बतायें।

Mr. Speaker: I think this question has been very well answered.

Bus Stand at Safidon

***1019. Chaudhri Ram Kishan:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any propoasal under consideration of the Government to open a depot of Haryana Roadways and also to construct a bus stand at safidon, if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized; and

(b) whether the Government is aware of the fact that old buses are plying in the Safidon area; if so, the time by which these are likely to be replaced by new ones?

मुख्य संसदीय सचिव(श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला):

(ए) सफीदों में इस समय डिपों खोलने का कोइ प्रस्ताव विचारधीन नहीं है। सफीदों में बस अड्डे के निर्माण के लिये भूमि का चयन किया जाना हैं भूमि के चयन तथा अधिग्रहण उपरान्त यहां पर बस अड्डे के निर्माण हेतु उचित पग उठाय जायेगें।

(बी) गाडियों की निर्धारित आयु 8 वर्श की है जबकि इस क्षेत्र में चल रही 61प्रति ात गाडिया 5 वर्श से कम आयु की हैं 6 वर्श से उपर आयु की कोई भी गाड़ी नहीं है। 8 वर्श की आयु पूरी होने के पश्चात पुरानी गाड़ियों को नई गाड़ियों में बदल दिया जायेगा।

चौधरी रामकि ानः मुख्य सचिव जी ने अभी बताया है कि सफीदों मे कोई बस डिपों खोलने का विचार नही है। अगर इनका डिपों खोलने का विचार नही है तो क्या वहां पर सब–डिपो खोल दिया जाएगा?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजलाः इस वक्त ऐसी कोइ प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री मांगे राम गुप्ताः चीफ पार्लिया मेंट री सैक्रेटरी साहब ने बताया है कि 61 परसैंट बसें 5 वर्श से कम पुरानी है लेकिन कल इन्होने बताया था कि जीन्द डिपों में सारे हरियाणा की खराब बसें है और वे टाटा कम्पनी की बनी हुई बसें है। इन्होने कल यह भी कहा था कि जीन्द में सबसे रद्दी बसें है और

घाटें म`चल रही है। क्या जींद में जो रद्दी बसें चल रही है उनका सुधार करने का कोई सरकार का विचार है?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजलाः जींद डिपों में सबसे अधिक घाटा है लेकिन उसका कारण यह नहीं है कि उसमें बसें सबसे अधिक खराब हैं।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, जब श्री जगन नाथ जी चीफ पर्लियामेंटरी सैक्रेटरी थे तो उन्होने गोहाना में जाकर के यह वायदा किया था कि गोाहाने के बस–स्टैण्ड को पक्का कर दिया जाएगा। अब मैं चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब से यह जानना चाहता हूं कि अब तक इस आ वासन को पूरा क्यों नही किया गया?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजलाः अगर श्री जगन नाथ जी ने ऐसा वायदा किया था तो उसको जरूर पूरा किया जायेगा।

चौधरी लाल सिंहः मैं चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब से यह पूछना चाहता हूं कि नारायणगढ़ एक पिछडी हुई तहसील है जिसमें कालका भी भाामिल हैं क्या यहां पर सरकार की कोई बस–स्टैण्ड बनाने की प्रोपोजल है?

श्री अध्यक्षः यह सवाल तो मेन प्र न से बनता नही है। फिर भी अगर आप जवाब देना चाहें तो दे सकते है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बतायेगें जैसे कि कल उन्होने बताया था कि कैथल डिपों में 13 लाख का घाटा है, क्या वह ठीक है?

श्री अध्यक्षः कल का जवाब कल आ चुका है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: मैं पूछना चाहता हूं कि जब हर डिपों में घाटा है तो क्या सरकार की प्राईवेट आपरेटर्ज को रूटस देने की कोई प्रपोजल है?

श्री अध्यक्षः यह अलग सवाल है, इससे यह सबंधित नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजलाः अध्यक्ष महोदय, यह तो अलग सवाल है। पिछले सै ान के दौरान श्री बूरा साहब ने एक काल अटैन् ान मो ान दिया था और इसके बारे में जवाब दे दिया गया था कि सरकार का प्राइवेट आपरेटर्ज को रूटज देने का कोई विचार नहीं है।

श्री मांगे राम गुप्ताः क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब की नौलेज में है कि सफीदों में, जिसका डिस्ट्रिक्ट जींद है, बस–स्टैण्ड के लिये जमीन एक्वायर की हुई है? अगर है, तो क्या कारण है कि सफीदों में अभी तक बस–स्टैण्ड की बिल्डिंग भी नहीं बनी है?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजलाः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली हमारी कोि ा ा यही है कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टरज पर बस–स्टैण्ड बनाया जाये। इस पालिसी के तहत जीन्द में पहले बस–स्टैण्ड बनाया जायेगा।

कामरेड भांकर लालः जिस वक्त श्री जगन नाथ जी चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी थे तो उन्होने सिरसा के नये बस–स्टैण्ड का उदघाटन किया था और यह एलान किया था कि यह जल्दी ही बनेगा। क्या वह बस–स्टैण्ड जल्दी बनेगा या नही बनेगा और बनेगा तो कब?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजलाः वह जरूर बनेगा। उसके लिये दफा 4 के नोटिस हो चुके है।

श्री देवेन्द्र भार्माः स्पीकर साहब, अभी चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब ने ऐ योरेंस दी है कि जो वायदे दिये गये है, उन्हें पूरा किया जायेगा। परन्तु मुझे भाक है कि वे वायदे पूरे भी किये जायेगें या नही। कई जगह श्री जगननाथ जी ने भी वायदे किये ओर दूसरे मिनिस्टरों ने भी किये है । क्या उन वायदों को पूरा किया जायेगा? अगर किया जाएगा तो कितने दिनों में किया जाएगा?

Mr. Speaker: If a Minister gives an assurance on the floor of the House then the Member should accept it as such (Interruptions & noise).

श्री देवेन्द्र भार्मा: मैं तो इतना जानना चाहता हूं कि कितने दिनो में उन वायदों को पूरा किया जाएगा?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, चण्डीगढ़ आनेवाली बसों को छोउकर झज्जर, महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी की सारी बसें टूटी हुई हैं क्या उनको सुधारने का सरकार का कोई विचार है?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: यह एक सैपरेट क्वै चन है। इसका आप अलग से नोटिस देदे आपको सूचना दे दी जाएगी। जैसा मैनें पहले भी बताया है कि 8 साल से ज्यादा पुरानी बसें किसी भी डिपों मे नही चलती है, 8 साल के बाद बस को कंडैम किया जाता हैं।

Suspension of officer/Officials in the Cooperation Department

***1925. Lala Balwant Rai Tayal:** Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a number of Class I, II and III officers/officials are under suspension present in the Cooperation Department, if so, since when; and

(b) whether charge sheets have been served upon them, if not, the reason therefore?

सहकारिता एवं दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) इस समय क्लास–1 का विभाग का कोई अधिकारी निलम्बित नहीं है। इस समय क्लास–II के अधिकारी और क्लास–III के 28 कर्मचारी निलम्बित है। एक सूची जिसमें उनके नाम और निलम्बन तिथियां दी गई हैं, सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ख) क्लास–I के अधिकारी को चार्ज भीट दे दी गई है। दूसरे क्लास–II अधिकारी को 28–2–79 को लिम्बित किया गया है और उसको चार्ज भीट यथा समय दे दी जायेगी। क्लास–III के 28 कर्मचारियों मे से 18 के केसों में फौजदारी मामले निहित है। इनमें से 13 केस कोर्टस के पास लम्बित है और 5 केस पुलिस के पास जांच अधी है। भोश 10 केसों मे से 5 कर्मचारियों को चार्ज ीट जारीकिएजा चुके है। दो कर्मचारियों पर चार्ज भीट जारी नहीं की जा सकी क्योंकि वे लापता चले आ रहे हैं भोश तीन कर्मचारियों को फरवरी, 1979 में लिम्बित किया गया हैं इन को चार्ज भीट जल्दी जारी कर दी जाएगी।

सहकारिता विभाग के निलम्बित (निम्बाधीन) अधिकारियों/कर्मचारियौं की वर्तमान सूची

कम संख्या	निलम्बित कर्मचारी का नाम	पद	कब से निलम्बित है

1	जसवन्त राय नैयर	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां (क्लास–II)	19.7.77
2	बलबीर सिंह	''	28.2.79
3	उदय सिंह	निरीक्षक सहकारी समितियां (क्लास–III)	21.278
4	चन्द्रभान सिंह	''	21.9.78
5	हेतराम	''	2.9.77
6	विजय बहादुर	''	14.2.79
7	गोवर्धन दास	उपनिरीक्षक सहकारी समितियां (क्लास–III)	5.3.68
8	जय सिंह	''	5.3.68

9	बनारसी दास	''	5.4.72
10	धर्म सिंह	''	5.5.73
11	अजीत सिंह	''	11.7.73
12	सोमदत	''	3.10.75
13	हरभजन	''	29.10.75
14	सुखबीर सिंह	''	4.10.76
15	ब्रह्मा नन्द	''	18.11.76
16	रतिराम	''	14.9.77
17	होि ायार सिंह	''	5.9.76
18	रघुबीर सिंह	''	23.9.77
19	दलीप सिंह	''	25.9.78
20	रणजीत सिंह	''	3.7.78
21	रमे ा चनछ	''	21.6.75
22	बीर सिंह	''	20.4.76
23	अमरीक लाल	''	29.1.76

24	लक्षमन कुमार	'' (आडिट)	16.10.76
25	रामनाथ	'' (आडिट)	12.5.2.79
26	हुकम चनद वधवा	सहायक (क्लास–III)	17.1.79
27	जय भगवान	लिपिक (क्लास–III)	1.9.69
28	बलराम		5.10.78
29	चरण दास	''	24.11.78
30	राधे लाल	''	1.2.79

लाला बलवंन राय तायलः स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि करनाल में एक रामचन्द्र मलिक नाम का व्यक्ति सस्पैंन्डिड है और वह 1972 से सस्पैन्ड चला आ रहा है। उसकों न तो नोटिस दिया गया है और न ही चार्ज भीट किया गया है। क्या यह बात मिनिस्टर साहब के नोटिस में है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैने अभी कहा है कि जो आदमी सस्पैन्डिड है उनकी सूची सदन के पटल पर रखी हुई है। यदि श्री तायल साहब इस सूची को देखने की

कृपा करेगें तो उसका नाम भी सूची में मिल जाएगा यदि सस्पैन्ड है।

लाला बलंवत राय तायलः इसमें तो इसका नाम नहीं है उसे 1972 में सस्पैन्ड किया गया था लेकिन अभी तक उसको न तो नोटिस दिया गया है ओर न ही चार्ज भीट किया गया है। मेरे पास जो लिस्ट आई है उसमें उसका नाम नही है। हो सकता है कि वह गलती से रह गया हो। मेरी सप्लीमैंटरी है कि उसको आज तक चार्ज भीट क्यों नहीं किया गया है?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, मेरे पास जो लिस्ट है उसमें भी वाकई रामचन्द्र मलिक का नाम नहीं है। हो सकता है कि गलती से रह गया हो। अगर उनके नोटिस में है तो वह अलग से लिख कर मुझे दे दे। उसकी इनक्वायरी करके इनको सूचना दे दी जाएगी।

श्री अध्यक्षः आप इनक्वायरी करके आनरेबल मैम्बर को बता दें।

लाला बलवंत राय तायलः स्पीकर साहब, मै आपकी मारफत मंत्री महोदय से मालूम करना चाहता हूं कि 1968 से दो आदमी सस्पैन्ड है ओर कुछ आदमी ओर 1972 और 1973 से भी सस्पैन्ड है। इतने लम्बे अर्से से गवर्नमेंट एम्पलाइज को सस्पैन्ड रखने का क्या मतलब है? क्या मिनिस्टर साहब इस बात पर रो ानी डालने की कृपा करेगें?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय यह बात ठीक है कि दो आदमी 1968 से सस्पैन्ड चले आ रहे है और एक आदमी 1969 से भी सस्पैन्ड चला आ रहा हैं उनके केस कोट्र में चल रहे है। कोर्अ ने यह केस वापिस कर दिये है क्योकि ऐसे केस सरकार की मंजूरी लेकर ही कोर्ट में आ सकते ह। सरकार की मंजरी लेने के बाद इन केसों को कोर्ट में रैफर करेगें इसलिसयें जो कोर्ट केसिज होते है उनमें सरकार की भी तो कुछ मजबूरी होती हैं

(10.00 बजें) चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, हरियाणा में खाद का बहुत बडा स्कैंडल हुआ हैं सरकार ने खाद के एक कट्टे पर 17 रूपये 25 पैसे की सबसिडी दी हैं इस सबसिडी का नाजायज फायदा उठाते हुये सोनीपत, गोहाना और पानीपत से अन्दाजन 200 ट्रक तरनतारन और अमृतसर में जाकर बिके और अकेले सोनीपत में लगभग 5 लाख रूपये की खाद का गबन हुआ, गोहाना में भी लाखों रूपये का गबन हुआ और जिन व्यक्तियों ने गबन किया।

श्री अध्यक्षः आप सीधा सवाल पूछें। मैं आनरेबल मैंबरज से रिक्वस्ट करूंगा कि सवाल छोटे और टू दी प्वांयट पूछें।

चौधरी गंगा रामः जिन लोगों ने गबन किया है उन्होने लिख कर दिया है कि हमारे से गलती हुई है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाहीनही हुई है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं

कि क्याउन के खिलाफ कोई केस दायर हुआ है, कोइ अरैस्ट हुई है या कोई व्यक्ति सस्पैन्उ हुआ है?

श्री अध्यक्षः यह सप्लीमैंटरी इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है, मगर मंत्री जी अगर जवाब देना चाहे तो दे सकते है।

चौधरी भजन लालः यह ठीक है कि दो कर्मचारियों के खिलाफ ि ाकायत आई थी, ये है सोनीपत के एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और दूसरे डिप्टी मैनेजर और ये दोनों सस्पैन्ड कर दिये गये है। इन दोनों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया जा चुका है।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, मैंने कहा है कि हाई लैवल पर यह स्कैंडल हुआ है। यह ठीक है कि दो आदमी निलम्बित किये गये है लेकिन इसमें हायर आफिसर्ज इन्वाल्वड हे और यह सकैंडल भिवानी तक हुआ है। क्या सरकार हाई लैवल के आफिसर्ज की इनकवायरी करवाएगी?

चौधरी भजन लालः इन्क्वायरी करवायेगें ओर जो भी हाई आफिसर इस इनक्वायरी में दोशी पाया जायेगा, उसको बख्भाा नहीं जायेगा, चाहे वह कितने बडे लैवल का व्यक्तिहो।

श्री फतेह चन्द विजः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि केसिज कोर्ट में चल रहे है और डिले के लिये ये मजबरे है। लेकिन जो केसलि 1972–73 से पुलिस के पास इन्कवायरी के लिये पैन्डिंग है, वे कितने दिनों तक पैंडिग रहेगें?

सात–सात साल हो गये है लेकिन उनकी इन्कवायरी नहीं हुई हैं क्या इसमें भी सरकार को मजबूरी है?

चौधरी भजन लालः आप बता दें कौन–2 से केसिज है। मैंने तो कहा है कि 5 केसिज पुलिस में है जिनकी जांच चल रही हैं आप जानते है कि अधिकारियों को इन्कवायरी के लिये बहुत–सा रिकार्ड इक्ट्ठा करना पड़ता है, कई जगह पूछताछ करनी पडती है, इस प्रौसैस में समय लग जाता है लेकिन हमारी पूरी कोि ा ा है कि मामल ेजल्दी से जल्दी निपटायें जाये।

श्री भले रामः क्या मन्त्री महोदय बतायेगें कि जो उन्होने दोआफिसर सस्पैंड किये है, वे पूरी इन्कवायरी करके सस्पैन्ड किये है या ि ाकयत मिलने के बाद तुरन्त उन्हें सस्पैन्ड कर दिया ग्या था?

चौधरी भजन लालः एक तरफ तो आप कह रहे है कि सस्पैन्ड करो दूसरी तरफ कह रहे है कि न करो। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन्कवायरी करके ही सस्पैन्ड किया है।

श्री अध्यक्षः इनकी डेटस रिप्लाई में दे रखी है।

लाला बलंवत राय तायलः 10 आदमियों मे से 5 को चार्ज भीट दी है और 5 को नहीं दी है, जिनको नही ंदी है, वे कौन–कौन से आफिसर्ज है?

चौधरी भजन लालः 3 कर्मचारी फरवरी, 1969 में सस्पैन्ड हुये थे, इनको जल्दी ही चार्ज भीट इ ू कर दी जायेगी।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, सरकार ने तमाम डिपार्टमेंटस को यह डायरैक ान दी हुई है कि 9 महीने से ज्यादा किसी कर्मचारी को सस्पैन्ड नहीं रखा जाएगा। या ो उसे चार्ज भीटइ ू की जाएगी या बहाल किया जायेगा। क्या यह डायरैक ान इस डिपार्टमेंट पर तुरन्त लागू करवायेगें क्योंकि इनको 9 महीने से ज्यादा अर्सा सस्पैन्ड हुये हो गया है?

चौधरी भजन लालः बहुत से केसजि कोर्ट में चल रहे है उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आदमियों को फरवरी में सस्पैन्ड किया हे उनको बहुत जल्दी चार्ज ीट इ ू कर देगें मैं हाउस को वि वास दिलाना चाहुंगा कि जो केसजि महकमें के पास पैन्डिग है, महकमा की तरफ से उनका निपटारा अगले 3 महीने से अन्दर अन्दर करने की पूरी कोि ा ा करेगें।

श्री भागी रामः मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंग कि रानिरयां कोआप्रेटिव बैंक में एक मिनी–बैंक मैंनेजर है जिसके खिलाफ 5–6 साल से खाद के गबन का केस है, इस केस की क्या पोजी ान है क्योकि इसका कोइ पता नहीं लग रहा है?

श्री अध्यक्षः वह सस्पैंडिड है।

श्री भागी रामः इस केस का बिल्कुल पता ही नहीं कि उसके खिलाफ केस चल रहा है या नहीं ?(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चौधरी भागी राम जी, इस सप्लीटमेंरी का इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है। किसी व्यक्ति के बारे में पर्सनल सवाल पूछना अन–फेयर है।

Imposition of tax fo patrolling by the police

***1005. Chaudhri Ude Singh Dalal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to impose any tax on the residents of cities for patrolling by the Police during night for their safety; and

(b)if not, whether the Government will introduce "THIKRIPEHRA' in cities as was prevalent in villages during Emergency days?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री वीरेन्द्र सिंह):

(ए) नहीं

(बी) नहीं

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अंग्रेजी राज की दी हुई 'ठीकरी–पहरा' की लानत को कब खत्म किया जाएगा? अग्रेंजी सरकार चली गई है ओर अब गांव के लोगों के मान–सम्मान का ध्यान रखना चाहिये। अब ठीकरी–पहरे की बेगार को खत्म करें। मैंमन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं भाहरों मे यह स्पै ाल

कन्सै ान क्यों है। कया इस ठीकरी –पहरे के सिस्टम को गावों से खत्म करने की कोई प्रोपोजल सरकार के विचारधीन है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः 1918 में स्माल टाउन ऐक्ट बना था जिसके तहत 10 हजार की आबादी से कम वाले गांव में ठीकरी–पहरा लगवा सकते है और यह इन गांवों की प्रोटैक ान के लिये लगाया जाता हैं जिस गांव की आबादी 10 हजार से कम है, वहां यह सिस्टम चला आ रहा हैं यह एक प्रथा है। सदन के सब मैंबर अगर चाहें तो सिटीज के लिये भी इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूं िक इस ऐक्ट को रिपील किया जाये। (विघ्न) अगर हाउस कामन ाा हो तो 1918 के स्माल टाउन ऐक्अ पर सिटीज के लिये विचार किया जा सकता है।

चौधरी ि िव राम वर्माः मंत्री महोदय ने बताया कि 10 हजार से कम आबादीवाले गांवों पर ठीकरी पहरा लागू करने की प्रथा है, इससे ज्यादा आबादी, वालों पर नहीं हैं एकतरफ तो सरकार फैमिली प्लांनिग का प्रचार करती हैं कि आबादी कम करों और दूसरी तरफ यह कानून है कि 10 हजार से जयादउा आबादी वाले गावों पर ठीकरी–पहरा नहीं लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा आबादी बढाओ और ठीकरी–पहरा की लानत से पीछा छुडाओ। (हंसी) इन दोनों बातों का तालमेल कैसा बैठेगा? क्य सरकार इसके बारे में सोच विचार करेगी? (हंसी)

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपकी माफत मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जहांपर 5 हजार की आबादी से कम वाले गांव है, वहां पर ठीकरी–पहरा के सिस्टम को तोडने पर विचार किया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंहः इस सवाल का जवाब आ चुका है।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि एक आदमी सारा दिन हल चलाता है, मजदूरी करता है और राम को पहरा देने के लिये उसको खडा होना पडता हैं अगले दिन फिर उस आदमी को खेत में जानापडता है, या मजदूरी करेन के लिये जाना पडता हैं ऐसे आदमी के लिये जनता सरकार क्या कर रही है। इस सिस्टम पर विचार करने के लिये क्यो न हाउस की रय ले ली जायें, क्योकि अब सारे मैंबर हाउस में हाजिर है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अगर हाउस के सब मैंबर चाहते है तो इस पर विचार किया जाएगा।

Revision of Pay&Scale of D.P.Es. and Librarians

***1049. Chaudhri HarSwarup Bura:** Will the Minister for Educaitonbe pleased to state wheter there is any proposal under consideration of the Government to revise the pay-scales of D.P.Es. and Librarians in the State?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरानन्द आर्य): हां।

चौधरी हरस्वरूप बुराः क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि ये क्या क्या ग्रेड है और यू0जी0सी0 ने क्या क्या ग्रेड रिकमेंड किये है?

यूनिवर्सिटीज				
1.	लाईब्रेरीयन्ज	1100—1600 से	1.	1500—2500
			2.	1500—2000
2.	डिप्टी लाईब्रेरीयन्ज	100—1250 से	1100—1600	
3.	असिसटेंट लाईब्रेरीयन्ज	400—950 से	100—1300	
कालेजिज				
लाईब्रेरीयन्ज	1.	100—950 से	700—1300	
	2.	400—800 से	700—1100	
	3.	300—600 से	550—900	

चौधरी हरस्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने बताया कि 300–600 वाले लाईब्रेीरयन का स्केल रिवाइज करके 550–900 कर दिया गया है लेकिन क्या वे बतायेगें कि इस रिविजन से उनको क्या फायदा हुआ है?

श्री हीरान्नद आर्यः यू0जी0सी0 ने जो रिकोमेंन्डे ान की थीउसके मुताबिक हमने कर दिया हैं 300–600 के स्केल को 550–900 का कर देने में भी अगर माननीय सदस्य कोई फर्क नहीं समझते तो यह बात मेरी समझ में नही आती।

श्री भले रामः क्यामंत्री जी बतायेगें कि इस वक्त स्टेट में कितने लाईब्रेरीयन और डिप्टी लाईब्रेरीयन्ज है और सरकार का इनके उपनर कितना खर्च आता है?

श्री हीरा नन्द आर्यः अगर यह सवाल ये अलग से करेगें तो मै अव य जवाब दूंगा।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, पिछले साल सारी स्टैट के डी0पी0ईज का डैपुटे ान चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने के लिये आया था। चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त के वित्त मंत्री श्री मलिक साहब को बुला कर कहा था कि उनकी मांगों पर गौर किया जाए। उसके बाद आपसे भी वह डैपुटे ान मिला था और आपने कहाथा कि इनकी मांगे सही है और इनका स्केल लैक्चरारज के बराबर कर दिया जाये। तो मै ि ाक्षा मंत्री जी से

पूछना चाहता हूं कि जब डी0पी.ईज. की डियुटीज लैक्चरारज से ज्यादा है तो उनको बराबर पे–स्केल देने में क्या रूकावट है?

श्री हीरानन्द आर्य: यू0जी0सी0 ने 1–1–73 से जो पे–सकेल रिवाईज किये है। वैसे उनकी क्वलिफिके न में भी अन्तर हैं एक थर्ड क्लास एम0ए0 तो डी0पी0ई0 हो सकता है लेकिन लैकचरार नहीं हो सकता। उनको इस पहलू से इक्वेट नहीं किया जा सकता।

Draining out the water of low lying places

***1042. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether this thing is kept in view at the time of digging a drain that it should be dug out from that area where it has a natural flow;

(b) if not, the reasons therefore together with the arrangement made for draining out thewater of low lying placesl and

(c) the time by which the bridge on the Indi drain near Hathlana village in district Karnal is likely to be constructed?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) हां, परन्तु कुछ मामलों पर मार्ग रेखा उंचे स्थान से भी की जाती हैं

(ख) कुछमामलों में मार्ग रेखा डाइवे ांन ड्रेन के तौर पर निचान वाले क्षेत्रों में बाढ़ के प्रकोप की अत्याधिकता को रोकने के लिये, उंचे स्थानों से भी की जाती है और ऐसे क्षेत्र का पानी, ड्रेन में पानी के लैवल के कम हो जानेपर निकाला जाता है।

(ग) 31—3—1980

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, मैने पूछा था कि क्या ड्रेन खोदते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसे उसी इलाके से निकाला जाए जहां पानी का कुदरती बहाव हो लेकिन मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि कुछ मामलों में मार्ग रेखा उंचे स्थानों से भी की जाती है। परन्तु मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस पालिसी से कुरप्ट अफसरों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और जहां वे चाहेगें वहां से ही पैसा इक्ट्ठा करके ड्रेन निकालने का सुझाव दे देगें?

श्री वीरेन्द्र सिंहः ऊंचे लैवल से जहां ड्रेन निकाली जाती है, वह बडे रेयर केसिज में होता हैं जहां डिप्रै ान पेचीदा हो और पानी निकलने की कोई संभावना न हो बल्कि पानी का टीब भर जाता हो उसको डाइवर्ट करने के लिये ड्रेन उंचे लैवल से लाई जाती है वरना आम तौर पर ड्रेन नीचे लैवल से ही निकाली जाती है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, पिछले सै ान में भी मैंने हाउस में यह बात कही थी कि छोटे अफसरना

की मेहरबानी से करेडा, असौला ओर भाना गांव में गलत जगह से ड्रेन निकाली जा रही है। कराडा और असौला में तो झगडा भी चला हुआ है और करोड़ा गांव वालों ने हाई कोर्ट में रिट भी कर रखी हैं क्या वजीर साहब इस झगडें को मिटाने के लिये चीफ इंजीनियर को मौके पर भेजने की कृपा करेगें?

श्री वीरेन्द्र सिंहः आप दरख्वास्त दीजिये, चीफ इंजीनियर मौके पर चला जायेगा (विघ्न)

श्री मूलचन्द मंगलाः क्या मंत्री जी बतायेगें कि पलवल में जो यू0पी0की 30–32 के करीब ड्रेन्ज है ओर जिनसे पानी नहीं निकल रहा है उनको सरकार ने साफ करवाने के बारे में कुछ सोचा है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः वेसे तो इस सप्लीमैंटरी का मुल प्र न से कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन फिर भी मै बता दूं कि गुडगांव में ड्रेन्ज का जितना काम हो रहा है उतना काम मेरे ख्याल से प्रदे ा के किसी हिस्से में इस समय नहीं हो रहा है।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, मेरे हल्के में मनोरपुर गांव से एक ड्रेन निकल रही है। उनके बार`में सभी गांव वालों ने, जहां से वह निकल रही है, लिख कर दिया है कि वह गलत जगह से निकाली जा रही है और उनको उससे कोई फायदा नहीं होगा। मंत्री जी से भी उन्होने यह बात कही थी। क्या मंन्त्री

जी बतायेगें कि लोगौं के रिप्रेजेन्टे ान को ध्यान में रखते हुये उस ड्रेन की अलाइनमैंट को चेंज किया जाएगा?

श्री अध्यक्षः इस सवाल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं हैं इस समय हरियाणा में सैकडों, ड्रेन्ज निकल रही है। इस तरह से एक एक ड्रेन के बारे में मिनिसटर साहब से जवाब पूछना ठीक नहीं हैं यह बडी नामुमकिन सी बात है।अगर इसके बारे में आप नोटिस दें गें तो ये अव य जवाब देगें। इस सवाल से सम्बन्धित कोई सप्लीमैंटरी अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते है।

चौधरी गया लालः मंत्री महोदय को मालूम है कि गुडगांव जिला में काफी ड्रेन्ज है। उनमें बहुत सी ड्रेन्ज यू0पी0 की भी हैं वे पूरी भर चूकी है। उसके न खुदने से वहां के लोगों को बडी परे ाानी है क्योंकि वहां पानी रूक जाता है। क्या सरकार का उनको खुदवाने का कोई विचार है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जिस एरिया मैं वे ड्रेन्ज है उसको अगर आप मेरे नोटिस में लएंगे तो आव यक कार्यवाही की जा सकती है।

चौधरी खुर ीदअहमदः कया मै मिनिस्टर साहब से पूछ सकता हूं कि इन ड्रेन्ज के बारे मे यू0पी0 सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में कोइ नैगोसिए ान चल रही है? स्पीकर साहब, आपको मालूम है कि यू0पी0 की कुछ ड्रेन्ज है तो हमारे एरिया में लेकिन कंट्रोल उन पर यू0पी0 का है। उनको टेक

ओवर करने के बारे में हरियाणा सरकार और यू0पी0 सरकार में कुछ नैगोसिए ान चली थी। क्या उस नैगोसिए ान में कुछ कामयाबी हुई है या नहीं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः वह नैगोसिए ान चल रही है।

चौधरी खुर ीद अहमदः वह कब तक खत्म हो जाएगी?

श्री वीरेनद्र सिंहः इसका अभी कोई जावाब नहीं दिया जा सकता।

चौधरी हरिचन्द हुड्डाः स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि लिकं ड्रेन्ज बनाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जहां जरूरत महसूस की जाती है वहां लिंक ड्रेन्ज के साथ के साथ बन रही है।

चौधरी राजेन्द्र सिहः अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कुछ नालियों खोदी जा रही हैं उनके विशय में मै सम्बन्धित अधिकारियों से मिला हूं लेकिन मेरी कोि ा ा करने के बावजूद भी वे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे है। इसलिये मै मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर मैं लिखित में कोई रिप्रैजैन्टें ान दूं तो क्या मिनिस्टर महोदय कन्सर्ड अधिकारियों का डायरेक्ा ान देगें?

श्री वीरेन्द्र सिंहः यदि आप मुझसे जबानी भी बात करेगें तो भी मैं डायरेक ान दे दूंगा।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, सारे हरियाणा में बहुत ज्यादा ड्रेन्ज और ऐप्रोच ड्रेन्ज बन रही है और इन सभी ड्रेन्ज को आठ नम्बर ड्रेन में डाला जा रहा है जो कि बादली हल्के में से गुजरती है। आगे दिल्ली सरकार इसको ऐक्सटेन्ड नहीं कर रही हैं तो मैं मिन्स्टिर महोदय से जानना चाहता हूं कि बादली हल्के के बारे में क्या प्रबन्ध किया जा रहा है? इस बारे में हर सै ान में पूछता हूं लेकिनसरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, दलाल साहब हर सै ान में बादली हल्के के बारे में सवाल करते है तो हम उनको जवाब भी देते हैं बादली हल्के का ज्रूर प्रबन्ध किया जायेगा।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाडियाः स्पीकर साहब, मेरे हल्के से सहबी नदी गुजरती हैं । क्या सरकारउस नदी को पक्का करने का इरादा रखती है?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिय गया।)

चौधरी ि िव राम वर्माः स्पीकर साहब, हरियाणा में ड्रेन्ज का बहुत अच्छा काम हो रहा है, इामें कोइ भाक नहीं है परन्तु मिनिस्टर महोदय ने मेरे प्र न के उत्तर में कहा है कि कुछ मामलों मे मार्ग रेखा, डाईव ान ड्रेन के तौर पर निचान वाले क्षेत्रों में बाढ के प्रकोप की अत्याधिकता को रोकने के लिये, उंचे

स्थानों से भी निकाली जाती है और ऐसे क्षेत्र का पानी, ड्रेन मे ंपानी के लैवल के कम हो जाने पर निकाला जाता है। मे। मिनिसटर महोदय से जानना चाहता हूं कि जो नीचे लैवल के खेत है उनमें पांच–साल दिन पानी खडा रह जाये तो क्या वे ुसलें खराब नहीं हो जाती है? यदि खराब हो जाती है तो क्या मिनिस्टर साहब इस बात पर फिर से विचार करेगें कि जहां से पानी का कुदरती बहाव है वहीं से पानी निकाला जाये यानि ड्रेन्ज खोदी जाये?

श्री वीरेन्द्र सिंहः रेअर केसिज में ही ऐसी ड्रेन्ज निकाली जाती है। जब कोई भी चारान हो तो उंचे एरिया से निकाली जाती हैं जहां ऐसा है वहां पांच–सात दि नही किसानों को दिक्कत होती है लेकिन जब कोई चारा ही ने हो तो ऐसा करना पडता है।

चौधरी सरदार खांः उजीना डायव र्ान ड्रेन्न खरीबी के पास से खराब हो गई है तो मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि उसको सही कराने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः वह सही कर दी गई है।

Loss suffered by the villages in Kurukshetra District

***949. Sardar Tara Singh:** Will the Minister for Revenue be pleased to state the estimated loss suffered by

villages Thaksaka Majra, Jakhwala and Adhoya due to flood in the Markanda River in Kurukshetra district during the years 1977-78 and 1978-79 and the amount of compensation paid to the farmers and villagers of the said villages during the afore-said period, year-wise separately?

Revenue Minster (Shri Preet Singh): A statement is laid on the table of the house.

Sr. No.	Name of the village	Year	Cropped area damaged	houses collapsed	Value of crops and house damage Rs.	Compensation Provided	
1.	Thaska Mirnaji. (Not Thaksaka Majra)	1977-78	10 Acres	-	Nominal	-	As the loss was less
		1978-79	210 Acres	-	45000	-	
2.	Jakhwala	1978-79	630 Acrs	62	330000	21300	Rs. 2000 for free distribution of Atta and Dal. Rs. 19300 for advancing taccavi loans for purchase of bullocks

							and fodder.
		1978 -79	630 Acres	30	675000	11900	Rs. 3900 as grant for house repair/reconstructio n. Rs. 8000 given as wheat seed loan 13 quilts were also given to the eligible persons.
3.	Adhoya	1977 -78	-	-	-	-	
		1978 -79	978 Acres	36	103200 0	32700	Rs. 9300 as grant for house repair/reconstructio n.
							Rs. 23400 has been given as wheat seed loan 31 quilts were also distributed.

	Total	1977-78	1210 Acres	62	330000	21300	
		1978-79	1818 Acres	66	1752000	44600	
Grant Total			3028 Acres	128	2082000	65900	

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, इन गांवों को जलबेहड़ा हैड से कम पानी डिस्चार्ज होने की वजह से काफी नुक्सान हो रहा है क्योकि वहां पर बाढ़ का पानी आ जाता है और उधर पंजाब और हरियाणा ने बान्ध बना दिये है। क्या मिनिस्टर साहब बतायेगें कि इस बारे में क्य प्रबन्ध किया जा रहा है?

श्री प्रीत सिंहः सरदार तारा सिंह का सप्लीमेंटरी इनररैलेवैन्ट है। उन्होने जो मेन क्वै चन किया है वह फ्लड रिलीफ के बारे में है अगर वे इस बारे में नोटिस देगें तो जवाब दे दिया जायेगा।

सरदार तारा सिंहः सम्बन्ध तो इसी सवाल से है।

श्री अध्यक्षः मिनिस्टर साहब कह रहे है कि बारे में नोअिस देगें तो जवाब दे दिया जायेगा।

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, मेरा तो बड सिम्पल सा सवाल है। इन गांवों की फसलों को बहुत नुक्सान हो रहा है इसलिये जलबेहड़ा हैड से जो पानी निकलता है उसके आगे उधर तो पंजाब का बान्ध लग जाता है ओर इधर हरियाणा का बान्ध लग जाता है जिस की वजह से पानी रूक जाता है और लोगों की फसलों को नुक्सान होता है। क्या मिनिस्टर साहब इस बारे मे कोई प्रबन्ध करेगें?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): जलबेहड़ा हैड से दस हजार क्यूसिक पानी डिस्चार्ज का प्रबन्ध किया गयाथा

लेकिन अब मारकण्डा का डिस्चार्ज बढ़ गया हैं उसकी री–माडलिंग के बारे में सोच रहे है।

सरदार तारासिंहः स्पीकर साहब, हरियाणा और पंजाब के दो बान्ध तो पहले ही बने हुये है और तीसरा बान्ध और बनाना भाुरू कर दिया है जिससे इन गांवों को बहुत नुक्सान होगा। क्या इस बारें में कोई प्रबन्ध किया जायेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंहः इस बारे में अर्ज कर दूं कि यह तो टैम्परेरी बान्ध हैं परमानेन्ट बान्ध नहीं है। जब जरूरत महसूस होगी तो उसको उखाड़ दिया जायेगा।

कामरेड भांकर लालः स्पीकर साहब, जिला सिरसा में घग्घर नही पर बान्ध बान्धे जा रहे है परन्तु 14–15 गांव रेलवे लाइन से पूर्व की और स्थित है वहां पर बान्ध न बधेंगें तो वे गांव बिल्कुल तबाह हो जायेगें क्योंकि उधर पंजाब सरकार भी उंचे बान्ध बना रही है जिससे इन गांवों को काफी नुक्सान होने की सम्भावना है। तो मै। मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इन गांवों में भी बान्ध बान्धे जायेगें?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, भांकर लाल जी को अपनी कांस्टीच्यूएंसी के गावों का ध्यान तो आया। वे हमारे पास उन गांवो की लिस्ट भिनवा दे उनका भी प्रबन्ध कर दिया जायेगा।

Exclusive institution for granting loans to the persons belonging to Backward Classes

***969. shri Jai Narain Verma:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether it is a fact that persons fbelonging to the Backward Classes are not entitled to get loans from Haryana Harijan Kalyan Nigam;

(b) if the reply to part(a) be in affirmative, whether there is any institution for granting loans exclusively to persons belonging to the Backward Casses, and

(c) if the reply to part(b) above be in the negative, whether there is any proposal under consideration of the Government to set up an institution exclusively for persons belonging to the Backward Classes for granting the loans?

Revenue Minister(Shri Preet Singh):

(a) Yes.

(b) The Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department given Loans to Scheduled Castes as well as to Backward Classes under the Scheme-

“Interest Free Loans for Various Trades”. However, there is no institution set up fro granting loans exclusively to Backward Classes.

(c) No.

सदस्य को निकालना

श्रीमती सुशमा स्वराजः राठी साहब आप हिन्हदी में उत्तर दें (विघ्न)

श्री अध्यक्षः जिस भाशा में मिनिस्टर महोदय जवाब देना चाहें दे सकते है। इस बारे में कोई आब्जैक ान नहीं हो सकता। (विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराजः अगर वे अग्रेंजी में जवाब देना चाहते है तो बे ाक दें लेकिन फिर सप्लीमेंटरीज का जवाब भी अग्रेंजी में देना चाहिये। (विघ्न)

श्रीमती भाान्ति देवीः हां जी, मिनिस्टर महोदय को हिन्दी में जवाब देना चाहियें (विघ्न)

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़ियाः राठी साहब को हिन्दी आती हे इसलिये उनको हिन्दी में ही जवाब देना चहिये। (विघ्न)

स्वामी अग्निवे ाः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब को हिन्दी में जवाब देना चाहिये।

Mr. Speaker: My ruling is quite clear on the subject कि मिनिस्टर साहब जिस भाशा में जवाब देना चाहें, दे सकते हैं । (विघ्न)

स्वामी अग्निवे ाः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब को हिन्दी में ही जवाब देना चाहिये क्योंकि हरियाणा की भाशा हिन्दी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः स्वामी जी आप बैठिये।

स्वामी अग्निवे ाः जब हरियाणा की भाशा हिन्दी है तो ये अंग्रेजी में क्या बोल रहे है?

श्री अध्यक्षः स्वामी जा आप बैठिये नही ंतो I will name you.

(Swami Agnivesh did not take his deat inspite of repeated directions by the Speaker)

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि हरियाणा प्रान्त की भाशा हिन्दी है, इसलिये मिनिस्टर महोदय को हिन्दी में जवाब देना चाहिये।

Mr. Speaker: Alright, remove Swami Agnivesh from the House.

(At this stage the Serjeant at-Arms went to the seat of the hon. Member, Swami Agnivesh, and requested him to leave the House as ordered by the Speaker. Swami Agnivesh then left the House.

तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now, the Hon. Minister may please complete his reply.

Shri Preet Singh: I repeat it.

(a) Yes.

(b) The Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department gifes loans to Scheduled Castes as well as to Backward Classes under the scheme-

"Interest Free Loan for Various Trads". However, there is no insititution set up for granting loans exclusively to Backward Classes.

(c) No.

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Scarcity of drinking water

***978. Shri Mool Chand Mangla:** Will the Minister for Public works be pleased to state-

(a) whether there is a scarcity of drinking water in Palwal constituency; and

(b) if so, the steps taken or porposed to be taken by the Government to remove the scarcity of drinking water?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(ए) भारत सरकार द्वारा निर्धारित नार्म्ज के अनुसार कमी नहीं है।

(बी) प्र न पैदा नहीं होता।

Tour of foreign counrtries

***993. Dr. Brij Mohan gupta:** Will the Chief Minsiter be pleased to state-

(a) the number of the Members of the present Vidhan Sabha sent by the Government on tour to foreign countries in the year 1978-79;

(b) the number of foreign countries visited by them according to the Scheduled tour programme;

(c) totoal expenditure incurred by the Government on the said tours; and

(d) whether any report was submitted to the Government by these members; if so, the broad details thereof?

Interim reply

अ0स0 कमांक 1 बी 151 राज(1पी)—79

देवी लाल

मुख्य मंत्री, हरियाणा

फरवरी 28, 1979

विशयः विधान सभा तांराकित प्र न नं0 993 विदे ाी यात्रा के बारे।

प्रिय कर्नल राम सिंह,

आप कृपया विधान सभा तारांकित प्र नों की सूची दिनांक 2–3–1978 की ओर ध्यान दें, जिसके अनुसार श्री बृज मोहन गुपता, एम0एल0ए0 द्वारा उपरोक्त विशय पर पूछा गया तारांकित प्र न सं0 993 उत्तर के लिये 2–3–1979 को देय हो गया है।

2. वर्श 1978–79 में विदे ाी यात्रा करने वाले एम0एल0एज0 के विशय मे वांछित सूचना राज्य के सभी प्र ाासकीय विभागों से तथा विधान सभा सचिवालय से एकत्रित की जा रही है। चूंकि सारी सूचना एकत्रित करने में समय लगेगा, अतः आप कृपया प्रश्न का उत्तर देने हेतू एक मास का समय बढ़ा दें।

आपका

ह/–

(देवी लाल)

कर्नल राम सिंह,

स्पीकर,

हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़।

Setting up Industries in Tehsil Safidon

***1020. Chaudhri Ram Kishan:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up some Industries in thesil Safidon; if so, the time by which the afore-said proposal is likely to be materialized; and

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to declare the said tehsil as anindustrially backward area, if so, the time by which it is likely on be done?

उद्योग मंत्री (डा0 मंगल सैन):

(क) जी नहीं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा जींद जिला पहले ही औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र घोशित है। भारत सरकार ने भी जिला जींद को रियायती वित्त के लिये औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र घोशित किया हुआ है परन्तु केन्द्रीय 10 प्रति ात–15 प्रति ात नकद अनुदान केवल जुलाना, जींद तथा उचाना ब्लाक में लागू है।

Illegal possession of liquor in Ambala Central Jail

***1006. Chaudhri Ude Singh Dalal:** Will the Minister for Jails be pleased to state whether some persons were recently found having illegal possession of liuor in Ambala Central Jail, if so, the action, if any, taken against them?

जेल मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): हां, देाशी बन्दियों की मुलाकातें एक सप्ताह की अवधि के लिये बन्द कर दी गई थी।

Unanimously elected Panchyats in the State

***1050. Chaudhri Har Swarup Bura:** Will the Minsiter for Development and Panchyat be pleased to state-

(a) the totoal number of Panchayats which have been elected unanimously in the State;

(b) the number of the Panchayats out of those referred to in part (a) above to whom the Government paid Rs. 5000/-, Rs. 3000/- or Rs. 2000/- respectively; and

(c) if the reply to part (b) above be in the negative, the reasons therefore?

Development Minister (Thakur Bir Singh):

(a) The districtwise total number of Panchayats unanimously elected during the recent panchayat election is as under:-

Sr. No.	**Name of the district**	**No. of Panchayats where the election of Panches/Sarpanches held unanimously be awarded Rs. 5000/-**	**No. of Panchayats where only Panches elected unanimously be awarded Rs. 3000/-**	**No. of Panchayats where only Sarpanches elected unanimously be awarded Rs. 2000/-**
1	Ambala	137	53	17

2	Kurukshetra	126	63	8
3	Karnal	81	30	2
4	Sonepat	23	18	3
5	Gurgaon	106	47	5
6	Narnaul	95	32	4
7	Bhiwani	81	23	4
8	Rohtak	40	33	5
9	Jind	55	47	1
10	Hissar	67	15	11
11	Sirsa	39	9	5
Total		**850**	**370**	**65**

(b) The amount of reward has not been givento any Gram Panchayat so far.

(c) The requisite amount of Rs. 55.00 lacs is being provide through supplementary estimate and is expected to be disbursed duringthe current financial year.

Construction of Grain Markets

***1043. Chaudhri Shiv Ram verma:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the Grain

Markets in the villages Nighdhu, Jamba and Kirmach of Nilokheri area, and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken in the matter?

कृशि मंत्री (ब्रिगेडियर रण सिंह):

(क) जी हां, सिवाये किरमिच के।

(ख) जहां तक किरमिच का सम्बन्ध है वहां पर पहले ही सब यार्ड खोला हुआ है ओर वहां पर अनाज मण्डी बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जाम्बा व निगदू में अनाज मंडी बनाने के लिये पूर्ण औचित्य जानने के लिये आव यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

T.A./D.A. draws by Chairman of Haryana Khadi Board

***1026. Rao Ram Narain:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the total amount of Pay, T.A. and D.A. drawn by the present Chair man of the Haryana Khadi Board since assumption of office to-date;

(b) the details of appointments made by him in the Khadi Board together with their break up district-wise;

(c) the total amount the present Chairman has spent on furnishing his office;

(d) whether he is entitiled to free residential accommodation; and

(e) if so, the amount of rent that is paid to him for his residence?

उद्योग मंत्री (डा0 मंगल सैन):

(क)

वेतन नीं परन्तु 1000 रूपये प्रति मास की दर से दिनाकं 16—5—1978 से 31—1—79 तक दिया गया मानदेय	8516.13 रूपये
दिनाकं 17—2—1979 तक दिया गया टी0ए0 व डी0ए0	9667.45 रूपये

(ख) विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) 6820 रूपये।

(घ) तथा (च) उनको 1000 रूपये तक प्रति मास किराये की सुविधा दी गई है।

विवरणी

अध्यक्ष खादी बोर्ड द्वारा बोर्ड में की गई नियुक्तियों का जिलावार विवरण

क्रम संख्या	पद का नाम	नियुक्ति का स्थान	संख्या
1	चपड़ासी	भिवानी	1
2	दैनिक मजदूर/चपड़ासी	मुख्यालय	3
3	जमादार	मुख्यालय	1
4	चौकीदार–कम–माली	मुख्यालय	1
5	लिपिक	सिरसा	1
6	स्टैनो/टाईपिस्ट	मुख्यालय	1
7	जिला निरीक्षक तेल उद्योग	भिवानी	1
		कुल	**9**

Water Supply sCheme in Jhajjar Assembly Constituency

***1000. Captain Mange Ram:** Will the Minister for Public Works bw pleased to state whether any water supply scheme for the supply of drinking water in Jhajjar Assembly Constituency has been prepared; if so, the details thereof together with the period by which it is likely to be implemented?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह): जी हां। ढाकला गांव में पीने के पानी की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। पाचं और गांव कोका, कुलाना, रत्नथल, असदपुरखेडा तथा सुबाना की योजना पर कार्य हो रहा है। सात अतिरिक्त गांवो के लिये अनुमान तैयार किया जा चुका है।

योजना को कार्यान्वित करने की कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि यह धन रा ि ा की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Illiterate children in the State

232. Swami Adityavesh: Will the Minister for Educaiton be pleased to state-

(a) the total number of illiterate boys and girls in the age group of 3 to 14 years during the year 1978-79 in the State; and

(b) the scheme formulated by the Government to make them literate together with the number of children included under the said scheme for making them literate?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरानन्द आर्य):

(क) लगभग 2348357 थी।

(ख) ि ाक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा यूनिवर्सलाईजे ान आफ एलीमैंटरी एजुके ान के अन्तर्गत स्कीम बनाई गई है और स्कीम के ड्राफट या मास्टर प्लान (मध्यावधि योजना 1978–83) के अनुसार 827000 अनपढ़ लड़के और लड़कियों को 1983 तक ि ाक्षा प्रदान कर दी जाएगी।

Report of Pipli, Nagina firing incidents

233. Swami Adityvesh & Rao Ram Narain: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether the report of the Enquiry Commission on the incident of firing at Nagina and Pipli has since been received by the Government;

(b) if so, the dsate on which the said report was received; and

(c) the action taken by the Government against the officers who were found guilty according to the findings of the said Commission?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(क) जी हां।

(ख) 17–8–1978।

(ग)(ए) निम्नलिखित सरकारी अधिकारियो/कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है:–

(1) श्री आर0एस0 अग्रवाल तथा श्री रणजीत सिंह, एच0सी0एम0।

(2) श्री जय सिंह तथा री चन्दन सिंह, पुलिस उप–अधीक्षक।

(3) श्री महिन्द्र सिंह, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।

(4) श्री बचना राम, श्री महाबीर प्रसाद, श्री धारा सिंह तथा श्री मंगल सिंह, सिपाही।

(5) श्री दया चन्द, गार्ड कमान्डर।

(बी) आयोग के निश्कर्शों के अनुसार दोशी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आरमी करने हेतू उनके विभागो को कह दिया गया है।

Construction of new roads in the State

234. Swami Adityavesh: will the Minister for Public Works be pleased to state the constituency wise totoal Kilometres of new roads constructed in the State during the period from 4th June, 1978 to 31st December, 1978?

Public Works Minister(Sh. Lachhman Singh): The required information is given in the attached statement.

STATEMENT

The process of road construction involves earth-work, collection of material for soling and wearing, laying, soling, laying and consolidation of wearing (metalling) and tarring surface and the work done during the period from 4-6-78 to 31-12-78 is given below. The road is considered as constructed when metalling is completed.

Sr. No.	Name of Constituency	Progress achieved from 4-6-1978 to 31-12-78					
		Earth Work	Collection of soling	Collection of stone Metal for wearing	Soling laid	Wearing laid (metalling)	Trarring
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Ambala District**						
1	Kalka	5.23	2.20	2.30	2.90	4.50	5.80
2	Naraingarh	1.02	1.40	1.40	4.05	1.83	2.40
3	Sadhaura	0.50	3.80	3.80	2.80	3.01	-
4	Chhachhrauli	0.50	1.90	0.20	6.21	6.13	1.86
5	Jagadhri	1.20	1.90	1.99	1.99	1.96	-
6	Yamuna Nagar	0.68	1.20	0.90	4.48	4.47	-
7	Mullana	0.60	0.10	0.10	0.10	-	-

8	Ambala Cantt	-	-	-	-	-	-
9	Ambala City	-	-	-	-	-	-
10	Nagal	-	5.04	5.20	4.29	1.99	0.60
Total		**9.73**	**17.63**	**15.89**	**26.82**	**23.89**	**10.66**
II. Karnal District							
11	Indri	5.20	2.48	1.53	0.48	0.48	1.50
12	Nilodkheri	1.40	0.85	0.50	0.85	0.35	-
13	Karnal	0.30	0.80	4.70	0.50	4.70	2.70
14	Jundla	3.50	1.17	-	1.17	1.17	1.40
15	Gharaunda	0.60	2.45	0.95	1.45	1.45	2.45
16	Assandh	1.00	-	-	-	-	0.60
17	Panipat	-	-	-	-	-	-
18	Smalkha	-	-	-	-	-	-
19	Naultha	0.50	2.50	5.75	1.50	-	-
Total		**12.50**	**10.25**	**13.43**	**5.95**	**8.15**	**8.65**
III. Kurukshetra District							
20	Shahabad	2.60	2.10	2.10	2.10	2.35	-
21	Radaur	1.20	-	-	-	-	4.20

22	Thanesar	0.10	3.70	5.00	3.20	3.92	3.10
23	Pehowa	2.30	3.22	3.52	2.72	2.70	1.27
24	Gulha	5.85	13.37	8.15	12.27	5.56	8.79
25	Kaithal	1.10	1.65	1.40	1.65	1.40	0.10
26	Pundri	-	-	-	-	-	-
27	Pai	2.45	0.80	0.50	-	-	-
Total		**15.40**	**24.84**	**20.67**	**21.94**	**15.93**	**17.46**
IV. Rohtak District							
28	Hassangarh	-	-	-	-	-	-
29	Kiloi	1.20	-	-	-	-	-
30	Rohtak	-	-	-	-	-	--
31	Meham	3.00	-	-	-	-	-
32	Kalanaur	0.40	4.00	4.50	4.00	4.50	2.00
33	Beri	2.20	-	-	-	-	-
34	Sahlawas	0.70	2.90	0.50	2.90	2.50	2.60
35	Jhajjar	-	0.70	2.00	0.70	0.50	1.80
36	Badli	-	0.20	-	0.20	-	-
37	Bahadurgarh	0.20	0.20	-	0.20	-	-
Total		**7.70**	**8.00**	**7.00**	**8.00**	**7.50**	**6.40**

V. Sonepat Disrict							
38	Baroda	1.40	1.40	3.40	1.40	4.20	8.06
39	Gohana	0.30	3.50	2.70	4.40	4.40	1.00
40	Kailana	-	-	-	-	2.20	-
41	Sonepat	-	-	-	-	-	-
42	Rai	-	-	-	-	-	-
43	Rohtak		-	-	-	-	
Total		**1.70**	**4.90**	**6.10**	**5.80**	**10.80**	**9.06**
Vi. Jind District							
44	Kalayat	0.50	7.50	2.80	5.70	-	-
45	Narwana	7.68	4.10	3.00	3.10	-	-
46	Uchana	-	-	-	-	-	-
47	Rajaund	7.20	-	-	3.20	-	-
48	Jind	-	-	-	-	-	-
49	Julana	2.80	0.20	-	-	-	-
50	Safidon	1.10	0.80	1.20	0.80	-	3.10
Total		**19.28**	**12.60**	**7.00**	**12.80**	**1.40**	**3.10**
VII. Gurgaon District							
51	Faridabad	-	-	-	-	-	-

52	Mewa Maharajpur	0.20	0.20	1.50	1.85	4.20	3.00
53	Ballabhgarh	0.92	-	-	0.32	-	0.32
54	Palwal	1.00	2.00	0.93	1.20	1.20	2.46
55	Hassanpur	-	0.50	0.50	3.40	2.77	2.77
56	Hathin	-	0.25	0.25	0.25	-	-
57	Ferozepur Jhirka	-	0.70	0.70	-	-	-
58	Nuh	0.40	3.05	3.05	4.98	3.47	-
59	Taoru	2.25	2.05	3.05	2.89	2.60	3.00
60	Sohna	2.00	1.87	0.40	3.37	3.47	4.47
61	Gurgaon	-	-	-	-	-	---
62	Pataudi	0.80	1.00	2.00	2.50	3.54	3.94
Total		**7.37**	**11.42**	**11.18**	**20.56**	**21.25**	**18.96**
VIII. Bhiwani District							
63	Bhadra	1.60	2.10	1.10	3.10	2.10	1.10
64	Dadri	-	-	-	-	-	-
65	Mundhal	0.50	1.13	1.86	1.13	1.03	-
66	Bhiwani	2.13	6.70	6.20	4.00	4.07	0.70

67	Tosham	-	-	3.00	-	6.15	3.00
68	Loharu	-	1.70	1.00	2.20	1.40	1.50
69	Bawani Khera	1.60	4.47	1.60	4.30	6.77	1.20
Total		**5.83**	**16.10**	**14.76**	**14.73**	**21.52**	**7.50**
IX. Hissar District							
70	Barwala	7.50	-	-	-	6.20	2.00
71	Narnaund	-	-	3.80	2.45	9.36	9.81
72	Hansi	-	-	0.60	-	2.08	-
73	Bhattu Kalan	4.50	-	-	-	-	-
74	Hissar	-	-	-	-	-	-
75	Ghirai	12.08	3.00	5.08	3.00	-	-
76	Tohana	3.45	5.45	3.60	4.95	3.10	-
77	Ratia	6.70	3.00	4.10	2.40	0.40	0.40
78	Fatehabad	1.30	-	2.00	-	1.00	-
79	Adampur	1.73	0.30	-	3.30	-	-
Total		**37.26**	**11.75**	**19.18**	**12.10**	**16.14**	**12.21**
X. Sirsa District							
80	Darba Kalan	6.35	6.55	8.55	5.85	6.65	13.15
81	Ellanabad	1.10	3.69	9.53	3.89	8.59	11.89

82	Sirsa	1.00	3.00	5.00	2.50	2.80	5.00
83	Rori	9.70	17.27	14.66	16.58	5.06	9.00
84	Dabwali	8.24	11.85	15.00	11.05	9.55	10.34
Total		**26.39**	**42.36**	**52.74**	**39.87**	**34.65**	**49.38**
XI. Mohindergarh District							
85	Bawal	0.50	3.75	2.25	2.25	2.00	-
86	Rewari	1.46	11.17	11.17	11.17	9.67	3.41
87	Jatusana	-	5.18	5.10	4.78	6.80	1.30
88	Mohindergarh	-	1.50	1.50	1.50	1.50	-
89	Ateli	-	0.50	3.20	0.50	1.50	4.00
90	Narnaul	1.60	1.00	1.00	1.00	1.40	1.50
Total		**3.56**	**23.10**	**24.22**	**21.20**	**22.87**	**10.21**
Grant Total		**146.72**	**182.95**	**192.17**	**189.77**	**184.10**	**153.63**

Bridge on Gaunchi Drain

235. Swami Adityavesh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bridge over the Gaunchi drain to link the Hathin and Reendka villages; and

(b) if so, the time by which it is likely to be completed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(ए) जी हां।

(बी) कार्य प्रारम्भ होने से लगभग 18 मास में पूर्ण होने की सम्भावना है। प्रारम्भ होने की तिथि फ्ण्डज की उपलब्धि पर निर्भर करती है।

वि ोशाधिकार भंग का प्र न

(At this stage several members rose in their seats)

Mr. Speaker: When I am on my legs, I would request the hon. members to please resume their seats.

Hon. Members, I have received a notice of a question of breach of privilege from Shri Shamsher Singh Surjewala, M.L.A. concerning a deliberate misleading statement made by Shri Ram Lal Wadhwa, Loacl Government Minister, on the 27th December, 1978, thereby committing a grave contempt of the privileges of the House.

Hon. Members, considering the seriousness of the matter, I have personally devoted great thought and have personally examined the case in the minutest of detail. I devoted atleast four hours yesterday going through the records of the sitting of the House held on the 27th December, 1978. I have also examined the documents and the motion submitted by Shri Surjewala and the documents submitted thereafter by Shri Ram Lal Wadhwa. While examining all these documents, I have constantly kept in mind the highest traditions of the

maintenance of democratic traditions followed by this August House as also the established traditions of the complete impartiality and fairness of the office of the Spaeker. Even so, I will briefly bring out the facts of the case before the House. These are as follows-

On the 27th December, 1978, Shri Shamsher Singh stated as follows-

''उपाध्यक्ष महोदय, जो लोकल बौडीज के मंत्री है, उनके खिलाफ आज करनाल के सी0जे0एम0 की कोर्ट में 193 आई0पी0सी0 के तहत कम्पलेन्ट दर्ज है। ''

इसके जवाब में श्री रामलाल वधवा, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब ने इस माफिक बोलाः

''डिप्टी स्पीकर साहब, चूंकि इनहोने हाउसमें मामला उठाया है इसलिये इन्हें बता देताह ूं कि कल दिनांक 26—12—1978 को सी0जे0एम0 साहब ने फैसला सुना दिया है और उस केस को डिसमिस कर दिया है।''

उसके बाद श्री भाम ोर सिंह ने कहाः

''अगर सी0जे0एम0 साहब ने वह फैसला दे दिया है तो भी कल से पहले तो यह मंत्री रहे, 8 महीने से मुलजिम होते हुये भी यहां विराजमान रहे।'' (विघन)

After some interruptions, Shri Ram Lal Wadhwa, Local Self Government Minister, again replied as follows:

"This was merely a complaint by some person. (Interruptions) Any person can file any complaint against any one."

In the end, Shri Shamsher Singh Surjewala again stated-

''वह किसी मामूली आदमी की कम्पलेंट नहीं थी बल्कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फारमर चीफ जस्टिस श्री ए0ड0 कौशल ने वह कम्पलेंट कर रखी थी। अगर आप बरी हो गये है तो अच्छी बात है।''

उसके बाद हाउस में काफी विघन यानी इन्ट्रप ान्ज हुई।

Now, Hon. Members, the pertinent facts as revealed after my detailed examination are as follows:-

While the notice of question of breach of privilege was under examination in my Secretariat, Shri Ram Lal Wadhwa also addressed a letter dated the Ist March, 1979, in theis regard. An examination of the documents attached with this letter reveals that there certainly was a case pending against Shri Ram Lal Wadhwa in the court of Chief Judicial Magistrate. this was heard and dismissed on the 26th December, 1978 and , as such, Shri Ram Lal Wadhwa did not make any false statement about the dismissal of thecase on the 26th December, 1978 in the court of the Chief Judicial Magistrate, Karnal. Further, the documents submitted alongwith the notice given by Shri Surjewala , M.L.A., have been examined by me. Rule 262 of the Rules of Procedure and

Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly states that if a notice refers toa adocument, the document should be attached with the notice. The documents submitted by Shri Surjewala are attested by him personally and not certified by the court. It is a normal procedure that the court's documents should be attested by the court from which they are obtained. The documents submitted by Shri Surjewala though attested by him are not attested by the court. On this ground alone, the documents are not maintainable. Further, Kaul and Shakdher in their widely accepted treatise on the Practice and Procedure of Parliament at page 252 have stated that a question of breach of privilege to be in order should contain a deliberate lie. In this particular case, the statement was made by the Minister on the spur of the moment and can by no stretch of imagination be termed as a deliberate lie.

Hon. Members, after giving due consideration to all these facts stated above, I hereby rule that this notice of privilege is out of order and hence I withhold my consent to raise this question of privilege.

श्री भाम ेर सिंह: * * * * * *
* * * * * * * * * * *
*

Mr. Speaker: I have given my ruling and I would reques the Hon. Member to honour the ruling given by the Speaker. If, however……

राव बीरेन्द्र सिंह: * * * * * *
*

Shri Shamsher Singh: * * * * *

Mr. Speaker: I have got the rule with me. You need not quote the rule. (Interruptions) I would only request the members to resume their seats. Whatever ruling I have given. I have given after a very very deliberate and through examination of the question. I am absolutely confident of my ruling. If thee is anything \further that the hon. Member would like to discuss with me, he may kindly do so in my chamber.

Shri Surrender Singh: Mr. Speaker.....

Mr. Speaker: On this matter I will not enter into any discussion. (Interruptions)Even this much privilege I gave because I wanted to give full and fair chance.

श्री सुरेन्द्र सिंहः * * * * * *

*(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चौधरी सुरेन्द्र सिह जी, आप बैठ जाइये। मैंने लगातार 4 घंटे लगाकर 27 तारीख को प्रोसीडिगज को स्टडी किया हैं (ाोर एवं व्यवधान) मैं सदन को बताना चाहता हूं। (ाोर) Please do not interruput. I would request the Hon'ble Members to sit down. मैने 27 तारीख की प्रोसीडिगंज को बडे गौर से चार घंट`लगा कर पूरी तरह से स्टडी किया हैं और मैं कंविनस्ड हूं कि चौधरी राम लाल वधवा ने कोइ फाल्स स्टेटमेन्ट नहीं दिया है।

श्री भाम ोर सिंहः * * * * * *

*

श्री अध्यक्षः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप बैठ जायें। (व्यवधान) If there is anything. I would request you to discuss it in my chamber.

श्री भाम ोर सिंहः * * * * * *

*

मुख्यमंत्री (चौधरी देवी लाल)* * * *

*

श्री अध्यक्षः मेरी रूंलिग के बाद कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं हो सकता हैं (ाोर) Tehre can be no point of order on the ruling.

श्री भाम ोर सिंहः * * * * * *

*

श्री अध्यक्षः मुझे चौधरी हरस्वरूप बूरा की ओर से (व्यवधान) No interruptions please.

राव बीरेन्द्र सिंहः * * * * * *

*

Mr. Speaker: Rao Sahib, please do not interrupt. I have given full opportunity. Please sit down when I am on my legs.

Rao Birender Singh: * * * * *
*

उद्योग मंत्री (डा0 मंगल सैन): * * * *
*

श्री सुरेन्द्र सिंहः * * * * * *
*

डा0 मंगल सैनः * * * * * *
*

श्री सुरेन्द्र सिंहः * * * * * *
*

डा0मंगल सैनः * * * * * * *

Mr. Speaker: I would request the Hon. Members to please sit down.

राव बीरेन्द्र सिंहः * * * * * *
*

Mr. Speaker: I would request the Hon'ble Members to sit down (Interruptions)

श्री सुरेन्द्र सिंहः * * * * * *
*

Mr. Speaker; Order please. iwould request the Hon Members to please take their seats.

वाक आउट

Rao Birender Singh: We are sorry, in protest we walk out.

Mr. Speaker: I can only request the hon. Members to please take their seats.

Rao Birender Singh: We have to show our protest against the injustice.

(इस समय सर्वश्री बीरेन्द्र सिंह राव, भाम ोर सिंह, दलीप सिंह राव, इन्द्रजीत सिंह, मांगे राम गुप्ता और नारायण सिंह एदनससे वाक आउट कर गये।)

मुख्यमंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, आपकी रूलिगं के बाद जो भी प्रोसीडिग्ज है वह ऐक्सपंज होनी चाहिये।

Mr. Speaker: After I gave my ruling, all the proceedings relating thereto should be expunged.

उद्योग मंत्री (डा0 मंगल सैन): स्पीकर साहब, मैं एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। स्पीकर का पद इस हाउस का सबसे डिगनीफाइड पद है और आप हमें कन्ट्रोल करते है चाहता आप यहां की डिगनिटी और डैकोरम के कस्टोडियन है। स्पीकरसाहब, गवर्नमेंट की पालिसी के खिलाफ तो वाक आउट समझ में आता है लेकिन अध्यक्ष की रूलिंग के खिलाफ वाक आउट करना is derogatory to the Chair. इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपको इसका नोटिस लेना चाहिये।

श्री अध्यक्षः मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मै अपने धर्म कर्म से जो भी काम करता हूं वह बिल्कुल इम्पारि ायल होकर काम करता हूं। इस नाजुक केस के अन्दर मै रिएलाइज करता हूं कि इस वक्त जो हाउस की सिचुए ान है और यहां पर ट्रेजरी बेन्चिज की औवर वेलमिग मैजोरिटी है इसलिये मैं अपनी तरफ से अपोजी ान बेन्चिज का जितना हक है उससे ज्यादा हक देता हूं। मुंझे इस बात का दुख है कि इतना गौर करने के बाद मैने फैसला दिया था और मेरी रूलिंग के बाद इतना भाोर भाराबा हुआ और मेंबर साहिबान ने वाक आउट किया। इसका मै बुरा नहीं मानता लेकिन मै इतना ही कह सकता हूं कि मुझे बडा दुख है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः स्पीकर साहब, मै एक दरखास्त करना चाहती हूॅ.....

श्री अध्यक्षः आप बैठिये।

ध्यानाकर्शण सूचना

19–2–1979 को बहादुरगढ़ उपमंडल के गांवों में तूफान से खड़ी फसलों के नश्ट होने सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः मुझे श्री हर स्वरूप बूरा, एम0एल0ए0 का काल अटैन ान नोटिस मिला है.....

स्वामी आदित्यवे ाः अध्यक्ष महोदय, मैने भी एक प्रस्ताव भेजा था। (ाोर)

श्री अध्यक्षः स्वामी जी आप बैठ जाइये। ...मुझे श्री हरस्वरूप बूरा, एम0एल0ए0 से भारी तूफान की वजह से 19–2–79 को बहादुरगढ़ सब–डिवीजन के लगभग 30 गांव, महम ब्लाक के दस गांव और नाहर सब तहसील के कुछ गांवो में दूर–दूर तक हुई तबाही के बारे में ध्यान दिलाओ प्रस्ताव का नोटिस मिला है। प्रस्ताव को मन्जूर किया जाता है आनरेबल मैंबर अपना प्रस्ताव पढ दे। रैवेन्यू मिनिस्टर अपना ब्यान देना चाहते है तो दे सकते है ओर अगर वक्त लेना चाहते है तो वह भी उनको दिया जायेगा।

सदस्य को निकालना

स्वामी आदित्यवे ाः अध्यक्ष महोदय, आगरा नहर के बारे में और उसकी माइनर के बारे में मैनें एक ध्यानाकर्शण प्रस्ताव भेजा था लेकिन अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला कि वह स्वीकार हुआ है या रिजैक्ट हो गया ळैं यह एक बडा अहम सवाल है। तीस गांवों को फसल तबाह हो गई है और पाचास लाख का नुकसान हुआ है। प ा और चारा आदि का काफी नुकसान हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः स्वामी जी आप बैठ जाइए otherwise I will name you. मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मैं हाउस में इंडिस्पिलिन कतई बर्दा त नहीं करूंगा और मै आपसे दरखास्त करूंगा कि जो मैनें रूलिंग दी है वह काफी विचार करने के बाद

दी है। (ाोर) स्वामी जी आप बैठ जाइये। जब मैं अने फीट पर हूं तो आपको बैठ जाना चाहिये। (ाोर)

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ तो जवाब मिलना ही चाहिये।

Mr. Speaker: I will name you, Swami Ji, please take you seat.

स्वामी आदित्यवे I: जो मामला मैनें भेजा है वह बडा जरूरी है आपको उस पर गौर करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी अगर आप नहीं बैठते हजै तो I name you.

स्वामी आदित्यवे I: स्पीकर साहब, वहां पर लोगों का बहुत नुकसान हुआ है.....

Mr. Speaker: You have been named. Kindly withdraw from the House.

(At this stage Swami Adityavesh left the House)

ध्यानाकर्शण सूचना (पुनरारम्भ)

चौधरी हरस्वरूप बूरा: मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की और दिलाना चाहता हूं कि 19–2–1979 को बहादुरगढ उपमंडल के लगभग 30 गांवों, मेहम ब्लाक के 10 गांवों तथा नाहर उप

तहसील के कुछ गांवों मे प्रचंड तथा भंयकर तुफान से दूर–दूर तक तबाही हुई।

इन गांवों में गेहूं, सरसों, चने, गन्ने की खडी फसलें पूर्णतया नश्ट हो गई है। बहादुरगढ उप–मंडल में 25 कि0मी0 लम्बे तथा 2 कि0मी0 चौडें कटिबन्ध में बहुत अधिक तबाही हुंई। करोर गांव में सरसों की फसल पूर्णतया नश्ट हो गई।

ओलों का वजन लगभग 100–200 ग्राम था। समस्त क्षेत्र एक फुट ओलों की गहरी चादर से ढक गया। इन गांवों के किसानों को सहायता के रूप में अनाज तथा अनुदान देने के लिये तुरन्त राहत कार्य किये जाए। इन्हें बिना ब्याज के ऋण दिया जाए। इसके अतिरिक्त आबियाना तथा राजस्व माफ किया जाये। ऋणों की वसूली एक वर्श के लिये स्थगित कर दी जाये। बिजली के बिलों की अदायगी यदि कोई हो उस समय तक निलम्बित कर दिये जाये जब तक कि पूर्ण हानि का पता न चले। छोटे छोट कियानों की सबसे अधिक हानि हुई।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुये)

श्रीमती सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न हैं आज जब स्वामी अग्निवे ा हिन्दी के मसले पर बोल रहे थे तो अध्यक्ष महोदय ने उनको सदन से चले जाने की आज्ञा दी और उनकी आज्ञा से वे चले गये। संसदीय प्रणाली के अनुसार मैं अध्यक्ष के आदे ा को चुनौती नहीं दे सकती हूं लेकिन मैं

प्रार्थना करना चाहती हूं कि स्वामी अग्निवे ा को और स्वामी आदित्यवे ा दोनों को वापिस बुला लिया जाये।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है, वे हाउस में आ जायें।

वित्त मंत्री का ध्यानाकर्शण सूचना के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मेरे माननीय दोस्त श्री बूरा ने हरियाणा में ओले पडने से जो नुकसान हुआ है उसके सम्बन्ध में हाउस की तवज्जुह दिलाई है। मैं सरकार की तरॅ से कहना चाहता हूं कि सरकार को इस आपत्ति पर बडा खेद है और जिस तरीके से पिछले सवाल ओले पडने से जिन इलाकों में नुक्सान हुआ था और जो रिलीफ पिछले साल दी गई थी वह तो तमाम रहेगी ही लेकिन उसके अलावा जिनका 75 से ज्यादा फसल का नुकसान हुआ है उन्हें तीन सौ रूपया फी एकड़ मुआवजा दिया जायेगा और जिनका पचास से 75 तक नुकसान हुआ है उन्हे दो सौ रूपया फी एकड़ दिया जायेगा और जिनका नुकसान 25 से 50 फीसदी तक हुआ है उनको 100 रूपया फी एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा। यह जो रियायत सरकार ने दी है, यह पिछले साल से ज्यादा है (तालियां)। इसके साथ मैं हाउस को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले साल बिजली के उपर जो सरकार ने तकावी द्वारा रियायत दी थी, वह इस साल भी दी जायेगी। (तालियों) इन

भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा

चौधरी खुर ीद अहमद (तावडू): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से यह तजवीज पे ा करता हूं कि गवर्नर साहब की खिदमत में मुदरजा जैल अलफाज में एक तहरीक पे ा की जाये:—

'कि हरियाणा विधान सभा के मेम्बरान जो इस सै ान में भाामिल हुये है, गवर्नर साहब के, उनकी तकरीर के लिये जो उन्होने 28 फरवरी, 1979 को अवाम के सामने दी हैख, तहदिल से भाुक्रगुजार है।'

डिप्टी स्पीकर साहब, गवर्नर साहब ने अपनी तकरीर में पिछले साल जो मुखतलिफ कामों पर खर्चा किया गया है, उसका जिकर यिका है। इसके साथ—साथ तमाम हरियाणा की हालात का नक ाा भी खींचा है और जो काम हमने आनें वाले साल में करने है, उन सब का जिक्र भी अपनी तकरीर में किया है कि आने वाले साल में हम ने क्या—क्या करना हैं गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रेस में हरियाणा को हर तरफ से आगे बढ़ता हुआ दिखाया है। एडमिनिस्ट्रे ान की सफलता एक नई रो ानी की तरफ एक कदम है लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जबसे हमारी सरकार का गठन हुआ है तब से हमारे सूबे पर सैलाब की एक ऐसी मुसीबत

आ पडी है जोकि हमारे सब के उपर एक लानत के तौर पर छाई हुई है, जिससे हम मुतासिर होते हैं देहातों में रहने वाले हमारे भाईयों के लिये यह मसला बडा अहम हो जाता है जिसका इलाज अभी तक नहीं हो पाया था लेकिन हमारी सरकार की कोि ा ाों और हमारे मेहनती इंजीनियरों के कारण, उनकी दिन रात की काम की लग्न के कारण अब यह मसला काफी हद तक हल हो गया हैं इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो प्लान बनाये है उसके मुताबिक लोगों को रिलीफ मिल गई है। हमारा गुडगांव का इलाका ऐसा था जहां पर बहुत सारा इलाका सैलाब के नीचे था लेकिन आज वहां पर हमारी सरकार और इंजीनियरों की मेहनत और लग्न के कारण काफी जमीन फसलों के नीचे है और अब वहां पर सब कुछ बोया जा सकताहै। इस साल हमारी सरकार ने जो बडी–बड़ी प्लान है। सरकारकी कई स्कीमों में से, मैं यहां पर एक स्कीम का जिक करना चाहता हूं जिसका नाम है उजीना डाइव र्न ड्रेन। इस ड्रेन के पहले हिस्सा को ही जुलाई, 1978 में तैयार करके चालू कर दिया गयाथा जिसके कारण गुड़गावं जिला के काफी सारे रकबें को सैलाब से बचा लिया गया है और अब वहां पर रबी की फसलें बोई जाती है। इससे पहले यह सारा इलाका पानी में डूबा रहता था। गुड़गांव में एक खिडवी गांव था वहां पर एक समस्या थी, वहां पर हर समय पानी उमड कर सामने खडा रहता था लेकिन अब हमारे लायक इंजीनियर्ज ने बडी मेहनत के साथ वहां पर काम किया है और वे वहां से पानी को निकालने में कामयाब हो गये है। मुझे पता चला है कि इस

साल वहां पर काम और तेजी स `चल रहा है और हमारे इंजीनियर्ज ने अमेरिका के इंजीनियर्ज से गाइडेन्स लेकर इस काम को पूरा किया है। पहले हम 400 क्युसिक पानी राजस्थान की तरफ निकालते थे लेकिन अब हम खुद ही 2200 कयुसिक पापनी को निकालने की ताकत रखते हैं इससे बडी कामयाबी सरकार की और क्या हो सकती हैं। इससे सारे हरियाणा के किसानों को राहत मिलेगी। इस ड्रेन पर जो भी काम हो रहा है वह सभी इंजीनियरों और हमारी सरकार की मेहनत और लग्न का नतीजा है। हमारे ऐक्सपर्टस ने जो मेहनत की है उसके कारण आज लोगों को सैलाब के तूफान से राहत मिली है। इसके साथ साथ जो दूसरे इलाकों में जैसे कि झज्जर, असन्ध और चुडानी भूपनिया वगै।रह पर फलड आता था, वहां पर चुड़ानी भूपनिया ड्रेन बनाकर सरकार ने रोहतक झज्जर के बहुत से इलाके को बाढ़ से बचा लिया है। इस समय झज्जर और असन्ध नगरों को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिये कार्यवाही की गई हैं 149 गांवों के गिर्द बनाये गये बांधों से गांवों की आबादियों का बहुत बचाव हुआ है। अब हालात यह है कि इन सभी इलाकों में सैलाब का पानी नहीं भी पायेगा और लोग बड़े आराम से अपनी जिन्दगी बसर कर सकेंगें। इसके लिये मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं क्याकेकि इसने फलड की जहनत को रहमत में तबदील कर दिया हैं लेकिन इस के साथ–साथ जो कंस्ट्रक ान का काम चल रहा है, उसके बारे में कुछेक बातें बडी सोचने वाली है। कंस्ट्रक ान, डिवीजन का जितना भी काम चल रहा है वहां बहुत सी चीजें लोहा, सीमेंट

ईटें वगैरह होती है। उस सारे सामान की हिफाजत भी सरकार को करनी चाहिये। इसके लिये मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि सरकार के पास एक स्टेट विजिलेन्स डिपार्टमेंट है जोकि केवल इन्ही बातों की छानबीन करता है और जहां पर गडबड़ होती है उसे सरकार के नोटिस में लाता है। कुछ जगहों पर जहां पर कि कंस्ट्रंक ान का काम चल रहा है वहां पर कुछेक ठेकेदार हेराफेरी करते है और कुछ लोग ऐसे है जो ठेकेदारों से भी उपर उठकर ऐसा काम करते हैं। पिछले दिनों एक केस पकड कर थाने में भी दिया गया था, यहां तक कि उस गाडी का नम्बर तक भी दिया गया जिस में सीमेंन्ट वर्गरह लाद कर ले जाया जा रहा थां। ऐसे केसिज काक विहजिलेन्स लेवैल पर रखा जाना चाहिये और इस डिपार्टमेंट को यह भी देखना चाहिये कि जिन ठेकेदारों ने अपनी कोठियां बनानी भुरू कर दी है और उन कोठियों में जो माल लग रहा है वह उनकी खून पसीने की कमाई है या कि उन्होने वह माल सरकारी गोदामें से या किन्ही ओर वकस से बचा कर वहां पर लगाया हैं। यह भी `दखना चाहिये कि उन्होने जो सीमेंट या ईटें अपनी कोठियों के लिये लगाई है, आया उस माल के लिये उन्होने कोई परमिट वगैरह लिया है या कि वैसे ही सरकार का माल गोल किया है ंइन सभी चीजों की तफसील इस सरकार के विजिलेन्स डिपार्टमेंट के जरिये हासिल होनी चचाहिये ताकि यह पता लग सके कि लोहा, सीमेन्ट और ईटें कहां जाती है और कैसे यह माल खाया जाता है। (विघ्न) इनत माम चीजों की तफती ा आप विजीलैंस के हवाले कीजिये जिसका जिक गवर्नर साहब ने

अपने ऐड्रेस में भी किया हैं जब सरकार के पास कप ान को रोकने के लिये एक साधन है तो उसको जरूर इस्तेमाल किया जाना चाहिये। बाकी किसी भी स्टैट के लिये और खास कर हरियाणा जैसी स्टेट के लिये जिसका दारोमदार देहात का जीवन है उसके लिये यह अहम मसला है कि उसकी जरायती पैदावार कैसे बढाई जाये। इसको बढाने के लिये बहुत सी चीजों की जरूरत पडती हैं मैं बताना चाहता हूं कि करीब 227 करोड़ रूपये का प्लान हमारी सरकार की तरफ से एप्रूव करवाया गया था उसमें बिजली पानी और सड़को बगैरह की सहूलियत भाामिल हैं इसके बाद सब से पहला काम मैं वह लुंगा जो एग्रीकल्चर महकमें के लिये जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास आबपा ाी के लिये पानी होना चाहिये और इसी वजह से जो पैसा प्लान के अन्दर रखा गया है उसमे से उसका 66 प्रति ात यानि 142 करोड रूपये इरीगे ान डिपार्टमेंट के लिये रखा गया हैं इरीगे ान के लिये जितनी स्कीमें है उन पर काम चल रहा हैं जैसे एस0वाई0एल0 जिसका ताल्लुक दूसरी स्टेट से है उसके बारे में आप अखबारों मे देखते है कि हमारी सरकार ने प्राइम मिनिस्टर से बात की है और इसके अलावा और भी कोि ा ा की है जैसे नेहरू लिफट स्कीम है जिससे उन एरियाज में पनी पहुंचेगा जहां के बुजुर्ग कभी यह सोच भी नहीं सकते थे कि इस एरिया में भी पानी पहुंच सकता है। इससे जिन इलाकों मे पानी की कमी थी उनमे पानी आएगा यानि वह रकबा भी अब नहरी पानी के सेराब के नीचे आ जाएगा।(विघ्न) कैथल जैसे इलाके में जहां फ्लड आता है उसके

लिये भी सरकार ने प्लान बनाया हैं इस साल यह भी स्कीम रखी गई है कि 18 हजार नये ट्यूबवैलों को कनैक्शन दिया जाये। बिजली की सप्लाई के लिये पहले जहां–जहां भी कमी उसकों दूर करने के लिये भी कोशिश की गई है और उसके लिये बहुत सी नई–नई स्कीमों को पूरा किया हैं इसके बाद जो कमी रह जाएगी उसवको पूरा करने के लिये भी सरकार सोच रही हैं एक एडी भानल थर्मल प्लांट की फरीदाबद में दिसम्बर 1979 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। उससे फरीदाबाद का इंडथ्स्ट्रयल एरियाऔर साथ वाला देहाती एरिया कवर होगा। बाकी पानीपत थर्मल प्लांट की स्टेज दो पूरा करने के बाद और एरियों को बिजली मिल सकेगी। यह तो उन स्कीमों की बात है जो हरियाणा के अन्दर चल रही है। इनके अलावा सरकार ने दूसरी स्कीमों में भी अपना हिस्सा लेने की पूरी कोशिश की है जैसे थी डैम प्रोजैक्ट से भी हमें हमाराहिस्सा मिले, दूसरे साल प्रोजैक्ट जो जे0एडं के0 में है और बैरासियूल स्कीम जो हिमाचल मे हैं और सिंगरौली ताप–बिजली स्कीमा जो यू0पी0 में चली रही है इनत माम स्कीमों मे हमारी सरकार ने हिस्सा लेने की पूरी कोशिश की है और काफी हद तक कामयाब भी हुई है। मैं आपके क्षरा यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे किसानों को पैदावार बढानें के लिये न सिर्फ पानी की ही जरूरत है बल्कि उनको फर्टिलाइजर की भी जरूरत हैं उस पर भी हमारी सरकार ने तीन करोड रूपये सबसिडी के तौर पर दिये है ताकि जिस वक्त किसानों को फर्टिलाइजर तकसीम हो उस वक्त उनको यह राहत मिल सके इसी प्रकार से

फसलों को जो बहुत प्रकार की बीमारयिां लग जाती है उनकी रोकथाम के लिये स्प्रे करने का भी इन्तजाम किया है। इसके अलावा किसानों को बीजाई के लिये स्टीफाइड सीड भी दिया गया है। एक समस्या जो बहुत ज्यादा है ओर खास क रवह नारायणगढ़ के इलाके में है। वहां पर जमीन को रिकलेम करने की जरूरत है। इस काम का चार्ज हमने ऐसे आदमी को दिया है जो इस बारे में काफी सूझबूझ रखते है। यानि लैंड रिकलेमें ान का काम बडी सूझबूझ के साथ चल रहा हैं इसके लिये हमें वर्ल्ड बैंक से भी मदद मिली है। रिकलेमें ान कार्पोरे ान के तहत 30 हजार एकड ऐसी जमीन दी गई है जो बिलकुल बेकार थी और उसको ठीक करने के लिये कार्पोरे ान काफी हद तक कामयाब हुई है। आज ये जो भी कदम उठाये गये है इनका नतीजा यह हुआ है कि हमारी स्टेट में जहां पिछले साल 55 लाख टन पैदावार हुई थी वहां इस साल 58 लाख टन पैदावार हुई है और अगर ये काम इसी तरह से चलते रहे तो आने वाले साल में यह 60 लाख टन तक पहुंच सकती हैं इसके साथ साथ किसानों की एक तमलीफ भी है कि जब वे अपना अनाज मंडियों में लेकर जाता है तो उसे बहुत दिक्कत आती है। जैसे इस वक्त आलू का सीजन चल रहा है ओर इसके बाद गेंहू का सीजन आएगा तो इन सीजनों के किसान की पैदावार मंडियों में पड़ी रहती है। मंडियों में इसलिये पडी रहती है कि हमारे पास ट्रांसपोट ान और स्टोर करने की पूरी व्यवस्था नहीं हैं मैं सरकार से गुजारि ा करूंगा कि वह हैफेड जैसी एजेंसियों को मंडियों में भेज कर ज्यादा से ज्यादा

खरीद करवायें । आज आलू की ज्यादा से ज्यादा खरीदकी जायें ताकि किसानों को राहत मिल सकें। इसके बाद हमारेसामने एक मसला और आएगा कि फुड कार्पोरे ान, हैफेड या कोइ दूसरी एजेंसी मंडियों में जो अनाज खरीदेगी उसको स्टारे करनरे का इन्तजाम अभी से करना चाहिये वरना किसान का अनाज कई–कई दिन तक मंडियों में सड़ता रहता है, इसलिये हमारी कोि ा ा यह होनी चाहिये कि जब भी किसान अपना अनाज मंडी में लेकर आये सरकार उसे फौरन खरीद कर अपने गोदाम मेंरख ले। किसान की इस दिक्कत को दूर करने के लिये कोआप्रेटिव सैक्टर का भी इस्तेमाल किया जा सकता हैं मैं अपने कोआप्रे ान मिनिसटर की तवज्जूह इस तरफ दिलाउंगा कि वर्ल्ड बैंक की मदद से अगर ऐसा इंतजाम किया जा सके तो बहुत बेहतर होगा। छोटी छोटी मार्किट के साथ भी अगर ऐसा इंतजाम हो जाये तो बहुत अच्छा है क्योंकि हमारी कोआप्रटिव सोसाइटियां मौजूद है उनके जरियें ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा कर गोदाम बनाने का यह काम हो सकता हैं आपकी स्टोर करने की इस वक्त जो कैपेसिटी है। वह करीब साढे 14 लाख टन की है जिसको कि और बढ़ाने की जरूरत है। इसी बात से किसानों को हर फसल पर कर्जों की जरूरत पड़ती हैं मे। इस बात का भुक्रिया अदा करता हूं कि सरकार ने जो कहा कि 14 परसैंट सूद घटाकर उन्होने 11 परसैंट कर दिया है। लोन पर यह जो तीन परसैट की छूट है यह बहुत बडी कामयाबी है लेकिन लोअर लैवल पर लोगों को लोन लेने के समय बहुत सी दिक्कते होती है। उसके लिये कुछ न कुछ मियाद होनी चाहिये ताकि

फसल के मौके पर अगर किसी किसान ने अपने पिछले साल के कर्जे को चुका दिया है तो उसको मीडियम टर्म या भाार्ट टर्म जिसमें कर्जा दिया जाता है उसमें उसको कर्जा दिया जाना चाहिये। कर्जा देने का मियाद फिक्स होनी चाहिये। 15 दिन या महीने के अन्दर उसको कर्जा दियाजाना चहिये । यह जो मिनि बैंक्स खुले हुये वहां के सेक्रटरी किसानों को बहुत तंग करते है। किसान अपने कागजात लेकर जाता है तो उसके कागजातो में कोई न कोई कमी निकाल दी जाती है। इस तरह उसको जो वह लोन चाहता है वह समय पर नहीं मिल पाता। किसान को 15 दिन या 20 दिन के अन्दर कर्जा मिलना चाहिये। मिनी बैंक का का सैक्रेटरी जो किसान के कागजों में एक भी गड़बड़ी निकाल देता है तो उसे दो दो महीने फिरना पड़ता है वह कभी ए0आर0ओ0 के पास जाता है तो कभी किसी अधिकारी के पास जाता हैं इन बैंको में तो उसको कर्जा मिलता है जो सैकेटरी को पसन्द है। उसको तो वह दोपहर से पहले एप्लाई करवायेगा और दोपहर के बाद उसको कर्जा भी दिलवा देगा। मैनेजर की यह ब्लेंक्ट अख्तियार नहीं होना चाहिये। किसान के पैसे का इन्तजाम 15 दिन के अन्दर होना चाहिये । उसकी लिमिट तय होनी चाहिये।

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल): किसान को कज्र 15 दिन के अन्दर मिलेगा। यह लिमिट हम फिक्स करने जा रहे है ताकि जल्दी से जल्दी किसान को कर्जा मिले।

चौधरी खुर ीद अहमदः यह लिमिट स्टैचुटरी होनी चाहिये। हमारे किसानों का केवल जमीन का मसला नहीं होता, उन्हें इसके साथ साथ मवे ाी भी पालने होते है, डैरी का भी काम होता है, मछली पालन का काम है और बहुत से अन्य कामों के लिये भी उन्हें मदद की जरूरत होती है। इन कामों के लिये डेरी डिवैल्पमेंट कारपोरे ान बनायी गई हैं उसको 25–30 करोड़ रूपया सालाना दिया है ताकि और चिलिंग सैन्टर या पलंट खोले जायें और दूध की पैदावार ज्यादा हौ। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसान को दूध की वह कीमत नहीं मिलती है जितनी उसकी लागत आती है। पहले उसका दूध पास के प्रदे ाों में लग जाता था। अब दूध का ऐक्सपोट्ट कम हो गया है। अब कम से कम उनका दूध दिल्ली जाता हैं सिर्फ दिल्ली जाने से घाटा हैं अब तो दिल्ली जाने पर भी पाबन्दी लगा दी गई है। इससे मिल्क प्रोडयुसर को नुकसान है। उसका एक ही सोर्स रह गया हैं इससे कम्पैरीटिवली किसान की दूध की प्रोडक ान कम हो जाती है। यह मोनेापली नहीं होनी चाहिये। इस मोनोपली में एक ही ऐजेंसी को दूध जाता है। इस तरह की मोनेपली से राज्य में करप ान होगी। इसलिये मैं फील करता हूं कि इस तरह की मोनोपली बिल्कुल नहीं होनी चाहिये। किसान की वही पहले वाली कैपेसिटी रहनी चाहिये। हिछली का एरिया हमे ाा खुला रखा जाये ताकि एक आदमी भी दूध ऐक्सपोर्ट कर सके। डिप्टी स्पीकर साहब, इसी तरह की आज बहुत सी बातें है। देहात का पढ़ा–लिखा तबका जिसको नौकरी नहीं मिलती उसको नौकरी पाना भी मुमकिन नहीं

है। अगर सब को हम नौकरी न दे सके तो उनके लिये छोटी–छोटी इंडस्ट्रीज खोलने का इंतजाम किया जाये। गवर्नर साहब के ऐड्रैस में कहा गया है कि रूरल एरियाज में वर्श 1978–79 में 330 यूनिटें खोलने का जो टारगेट था वह पूरा कर लिया जाएगा। ताकि देहात में रहनेवालो को जहां लेबर चीप मिल जाती है, रोजगार मिल सके। गवर्नर ऐड्रैस में यह भी कहा गया है कि अगले पांच सालों में 1900 युनिट्स स्थापित करने की कोि ा ा की जायेगी। इन लोगों को टैक्नीकल गाइडैंस देने का भी इंतजाम किया जायेगा। एक देहाती इलाके में देहात का एक नवयुवक जब इंडस्ट्रियल यूनिट खोलना चाहता है तो उसको लोन देले के लिये दिक्कते होती है। कई गांव ऐसे है जहां बैंक नजदीक नहीं है उनको यह कह दिया जाता है कि बैंक 10 किलोमीटर के एरिये में ही लोन दे सकता हैं जो गांव बैंक के 10 किलोमीटर के एरिये में नहीं आता है उसकी डिफीकल्टी को दूर करके ज्यादा से ज्यादा इंडस्टरी गांव में लगायें औरउसको टैक्नीकल गाईडैंस दी जाये । देहात में जो टैक्नीकली एक्सपर्ट है उनको लगाया जाये। टैक्नीकली एक्सपर्ट लग रहे है और लगे हुये है उनको देहात में भेजा जाये ताकि देहात के लोगों को गाइडैंस लेने के लिये चण्डीगढ़ न आनापड़े। बड़े कारखानों को लगाने के लिये ह मदस एकड़ जमीन देते है जबकि एक बडा कारखाना केवल तीन चार एकड में ही लगा लिया जाता है। बहुत हुआ कोई बहुत बडा कारखाना लगायेगा तो दस एक डमें से तीन चार एकड जमीन पर लगा लेगा परन्तु इसके अलावा तो बाकी जमीन बरबाद

होती है। उसमें कोइ प्रोडक ान नहीं होती है वह बेकार पडी रहती है। वे तो इस दस एकड़ जमीन के रकबे पर पूरा कब्जा कर लेते है, और कारखाना सिर्फ एक कोने में लगा हआ पाया जाता हैं। फरीदाबाद, गुड़गांव मेंकई बडी बडी इंडस्टरीज लगी हुई हैं अब धारूहेड़ा में भी लगी है। लेकिन अभी तक उनमें कोई प्रोडक ान भुरू नहीं हुआ है। जिन लोगों से ये जमीने एक्वायर की थी उनसे तो तीन रूपये गज खरीदी गई थी और कारखानेदारोंको 60 रूपये गज तक बेची गई। इसतें सरकार को फायदा हुआ। सरकार ने तो अपना फायदा सोचा अब वही जमीन लाखों के दाम पर मिलती है। (विघ्न)

एक सदस्यः आपकी केवल दो जिलों पर ही नजर क्यों है?

चौधरी खुर ीद अहमदः दोजिलों पर नजर इसलियें है क्योकिं आप जैसे लोग दिल्ली में रहते है ओर इन जिलों को दिल्ली नजदीक पडती है इसलिये सब ने इन्ही दोजिलों में कारखानों के लिये जमीन ले ली है। आप लोग फरीदाबार और गुड़गाव पर ही गब्जा कर रहें है। ऐसे बड़ेबड़े कारखानों को लगाने की पाबन्दी होनी चाहिये जिनसे केवल जमीन पर कब्जा हो और प्रोडक ान न हो। ये सरमायेदार लोग मजदूर के हक की बात नहीं करते हैं वे अपना सरप्लस रूपया लगाकर जमीन पर कब्जा कर लेंते है। सरकार को उतनी ही जमीन देनी चाहिये जितने पर प्रोडक ान हों अब इसी प्रकार सरकार ने पानीपत में

फर्टेलाइजर का कारखाना लगाया है। सरकार के अनुसार यहां खाद का उत्पादन भुरू हो गया हैं अब हमें देखना है कि सरकार इसमें कितनी कामयाब होती हैं

अब मैं एक और चीज की तरफ आपकी मारफत सरकार का ध्यान दिलान चाहता हूं। वह है ऐजुके ान के बारे में। बहुत से गांवो में प्राइमरी स्कुलों को मिडल स्कूल बनाने की जरूरत है और मिडल स्कूलों को हाई स्कूल बनाने की जरूरत है यानि इनको अपग्रेड करने की जरूरत हैं सरकार ने पिछले साल 71 स्कूलों को प्राइमरी से मिडल बनाया था और 40 मिडल स्कूलों को हाई स्कूल लेवल पर लाया गया लेकिनयह काफी नहीं है। ऐजुके ान के उपर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च होना चाहियै। बच्चों की तालीम की सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार को यह भी देखना चाहिये कि स्टेट में ऐजुके ानल इम्बैलेंसिज पैदा नहीं होने चाहिये। कुछइलाके तो ऐसे है जिनमें तालीम काफी हद तक बढी हुई है और कुछ इलाके ऐसे है जिनमें तालीम सिर्फ नाम मात्र ही मौजूद है। यह नहीं होना चाहिये कि हर हल्के के लिये यूनिफार्म रूल बनाये जांए कि हर हल्के मेंदो स्कूल अपग्रेड होगें। अब लीजिये जैसे श्री मूलचन्दजैन जी करनाल में रहते है वहां भी दो स्कूल अपग्रेड होगें। लोहारू में भी, क्योंकि वहां हमारे ऐजुके ान मिनिसटर साहब रहते है, दो स्कूल अपग्रेड होगें । ऐसे ही रोहतक में भी दोस्कूल अपग्रेड होने चाहिये। सरकार को अपग्रेडे ान के वक्त यह देखना चाहिये कि किस इलाके में

कितनी तालीम की जरूरत है ओर कितनी इस समय वहां मौजदू हैं गवर्नमेंट के ऐजुके ानल इंस्टीच्यू ांज को ध्यान में रखते हुये ऐजुके ान इम्बैलेसिंज को दूर यिका जाये और जो ऐसे इलाके है जिनमें काम भाुरू है, जिमें यूनिवर्सिटियां पहले से ही मोजूद हे, जिनमें काफी स्कूल भी है, जिनमें माडल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है और कालेज है ओर बहूत से प्राइवेट स्कूल खोल सकते है ऐसे इलाकों को छोड कर गवर्नमेंट उन इलाकों की तरफ ज्यादा ध्यान दे जहां पर ये सुविधांए नहीं है। दूसरी प्वायंट हाई स्कूल ऐजुके ान के बारे में हैं प्राइवेट कालेजों के लिये जो यह फैसला किया गया है इनको 75 परसैंट पैसा डैफीसीट को मीट करने के लिये दिया जाएगा, यह बहुत ही अच्छा कदम है। दरअसल यह होना चाहिये जैसा कि मैने प्राइमरी ऐजुके ान के बारे में कहा हैं। इस तरह से कालेज ऐजुके ान पर भी सरकार की ही जिम्मेवारी होनी चाहिये। अब सरकार जो 75 परसैंट ग्रांट देती है यह 75 परसैन्ट की बजाये 95 परसैन्ट दी जानी चाहिये।

इसके बाद मैं एक और बात कहना चाहता हूं जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। टैक्नीकल ऐजुके ान इस स्टेट में लोअर लैवल पर प्रोवाइड की जाए ताकि जो थोड़ी तालीम वाले लोग है वह अपनी टैक्नीकल ऐजुके ान हासिल कर सकें और अपना रोजगार कमाने के काबिल हो जाएं। इस काम के लिये जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जायेगा वह हमारे लिये मुफीद साबित होगा और हरियाणा में जो अनएम्प्लायमेंट की समस्या है वह दूर

होगी। इससे गरीब तबके का भी काफी हद तक सुधार हो सकता है। यह जो अनाज के बदले काम की स्कीम है जिसका अभिभाशण में जिक्र किया गया है वह काफी हद तक बहुत सी छोटी–2 जरूरतों को पूरा भी कर देगी और गांव के गरीब लेागों का इससे थोडा बहुत गुजारा भी होता रहेगां सब्जी की का त और मुर्गीपालन की जो स्कीमें है यह बहुत अच्छी है। दिल्ली के आसपास बसने वाले इलाकों में इस पैदावार को आसानी से दिल्ली की मार्केट में भेजा जा सकेगा। हमारी सरकार ने दिल्ली के आसपास 40 मील के एरियेके इलाकों के लिये जो पैसा रखा है यह एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। इससे रोजाना दिल्ली की मार्केट में वह चीज सप्लाई की जा सकती है। अगर यह 40 मील की हद हट जाये या इसको दूर कर दिया जाये तो हरियाणा को अपनी वस्तुओं से कमाई करनें के लिये साधन मुहैया हो जाता है। इसके बाद गांव के लोगों की जो सबसे बडी जरूरत है वह वाटर सप्लाई की है, पीने के पानी की है। जिन गांवों में पीने का पानी नहीं है उन गावो को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार ने वर्श 1978–79 में तकरीबन 125 गांवों को एक साल के अन्दर–2 पीने का पानी दिया हैं सरकार का यह एक बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा सरकार ने अगले साल के लिये जो गांव रखे हे वह 170 गांवों की प्लान रखी हे। इसके अतिरिक्त इसी साल नलों द्वारा 190 गांवों को जो पीने का पानी देने का प्रस्ताव है यह भी एक बहुत ही सराहनीय कदम हे क्योंकि बहुत से गांवों मे पीने के पानी की बहुत दिक्कत थीं वर्श 1977 तक हरियाणा में 930 गांवों

को पीने का पानी दिया जा चुका था और अब 190 गांवो को पानी दिया जाना बाकी है। मैं सरकार को मुबारकिवाद देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जितने भी गांव अगलेसाल में रखे है उनको भी पीने के पानी सुविधा जल्दी दी जाएगी। यह एक ऐसा कदम हे जिसका असर गांव के लोगों की जिन्दगी पर बहुत अच्छा पड सकता ह। दूसयरा सरकार ने 1982 तक हर गांव को सडक देने का प्रोग्रम रखा ह। सडक और बिजली के बिना गांवों की तरक्की नहीं हो सकती हैं वर्श 1982 तक हर गांव कोसडक से कनैक्ट करने से हमारा यह पैसा बहुत अच्छे प्रोजैक्ट पर खर्च होगा। इन भाब्दो के साथ मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सी जो ऐसी चीजे है जिनका जिक्र मेरे साथी कर सकते है, और कह सकते है कि यह चीज नही`ं होनी चाहियें और ऐसा हमारे सामनेआया भी है कि बहुत सी चीजों काजिक्र हमारे गवर्नर साहब करना भूल गये है। लेकिन मैं बता दूं कि ला एंड आर्डर की सिच्यूए ान का बडा मसला है जिसका जिक्र इसमें किया गया है उसमें लिखा गया है कि पूलिस अमले को बढाया गया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी स्टेट में जरायम ज्यादा हुये है बल्कि कानून तथा व्यवस्था को और ठीक ढंग से चलाने के लिये अमले को बढाया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि हरिजनों को, सफाई कर्मचारियों को सहूलियतें दी गई है। यह बात ठीक है। हर म्यूनिसिपल्टी के पिछले बजट में बहुत से कर्मचारियों को सहूलियतें दी गई । इसके अलावा हरिजनों के लिये जो चौपाल का प्रोग्राम था उसके लिये भी सरकार ने बहुत कुछ किया है

क्योंकि अच्छी पोजी ान हरिजनों को गांव में दे दी है। इसके अलावा और भी चीजें है जिनका अच्छी तरह से इंतजाम किया गया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, गुड़गांव जिला में मेवात का एक कम्पैक्ट एरिया है। वहां पर एक माइनोरिटी कम्युनिटी है। वहां पर सी0एम0. साहब त ारीफ ले गये थे और नूंह के मुकाम पर उन्होने ऐलान कियाथा कि इस कम्युनिटी को सर्विसीज में 10 परसैंट रिजर्वे ान की जायेगी। उन्होने बडी दियादिली से इस बात को कबूल किया था कि इनके लिये रिजर्वे ान होनी चाहिये। इन्होने उसी स्टेज पर बोलते हूये एलान किया था कि जल्दी से जल्दी इस तरफ कदम उठाएंगे और इस अ योरेंस को पूरा करने की कोि ा ा करेगें। यह एलान करके उन्होने मेवात के अन–एम्पलायड यूथ्स की बडी मदद की है ओर यह इस माइनौरिटी के लिये बडी सैटिस्फैक ान की बात है। कांस्टीच्यु ान के तहत इस माइनोरिटी कम्पुनिटी के लिये स्पै ाल प्रोवीजन नहीं किया जा सका, लेकिन सरकार अपने जराये को इस्तेमाल करके इनको सहूलतें देगी ताकि वहां के लोगों को एम्प्लायमेंट के पूरे चांसिज मिल सकें। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार ने अपने प्रोग्राम की झलक, जो गवर्नर ऐड्रेस के जरिये हाउस में पे ा की है , उसकी मैं पुरजोर ताईद करता हूं और जिस वक्त हाउस में यह मत पास हो जाये, भाुकिया का पैगाम पास हो जाये तो गवर्नर साहब को भेज दिया जाये।

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला कैंट): मेरे भाई श्री खुर ाीद अहमद द्वारा रखे गये प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिये खडी हुई हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का अभिभाशण सरकार की उपलब्धियों, सरकार के कार्यक्रमों और उसकी नीतियों का घोशणा–पत्र होता है जो राज्यपाल के अभिभाशण द्वारा सदन में घोशित किया जाता है ओर सदन के सदस्यों को मालूम पडता है कि चालू वित्त वर्श के अन्तर्गत सरकार ने क्या–क्या प्रोग्राम बनाये और अगले साल के लिये क्या कार्यक्रम तैयार किये हैं संसदीय प्रणाली में यह रिवाज चला आ रहा है कि राज्यपाल का अभिभाशण सरकार द्वारा ही तैयार किया जाता है और भाशण में कही गई सारी बातों की जिम्मेदार सरकार की होती है ओर सब बातों के लिये जवाबदेह भीसरकार ही होती है। इसलिये मैं राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करती हूं ओर भाई खुर ाीद अहमद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। राज्यपाल महोदय ने आना बहूमूल्य समय निकाल कर हमारे सदन के सदस्यों को सम्बोधित करने की जो कृपा की है, मैं उनका धन्यवाद करती हूं, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं सरकार का ध्यान, इस अभिभाशण मे कही गई कुछ एक बातों की और आकर्शित करना चाहूंगी। उपाध्यक्ष महदेय, सबसे पहले मै एक टिप्पणी इस अभिभाशण के बारे में करना चाहती हूं। अगर एक नजर से इस सम्भाशण को देखा जाये, एक झलक से देखा जाये तो ऐसा मालूम होता है कि पिछले 30 वर्शो से काम करने का एक ढर्रा चला आ रहा है और उस ढर्रे से, उस दायरे से हमारी सरकार निकल चुकी है और काम करने

का अपना दायरा बदला हैं एक झलक सामने यह आती है कि आज हमारी जनता सरकार ने अपनी पूंजी का रूख भाहरों से हटाकर गांवों की तरफ मोड़ा है और गांवों में सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करेगी। आज तक सदियों से उपेक्षित वर्ग, वि ोश तौर पर किसान वर्ग कोजयादा से ज्यादा आर्थिक राहत देने की कोि ा ा इन जनता सरकारने की है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस अभिभाशण को पढ कर मुझे लगा कि यह भाशण, जयादातर सरकार के वायदों या आ वासनों को रोटीन स्टेटमेंटस पर आधारित हैं इसमें सरकार की प्रगति को आंकडाबद्ध करनेकी कोि ा ा नहीं की गई। मेरा सरकार को यह सुझाव है कि अगर सरकार प्रान्त में की गई प्रगति को आंकडों में बांध देती तो बात करने का वजन बढ़ जाता है। इसमे पैरा 11, 24 और 28 ऐसे पैराग्राफ है नि में देहातों मे ंबनाये जाने वाले हस्पताल, सरकार द्वारा चालू किये जाने वाले गृह–निर्माण के कायक्रम पर केवल घोशणा–मात्र की है, आकंड़े नहीं दिये गये। यह तो एक ढर्रे की बयानबाजी है कि जलमार्ग पक्के किये जा रहे है, सड़के पक्की की जा रही हैं इन पैराग्राफस को बारबार पढ़ कर ऐसा लगता है कि जैसे कि सरकार ने घोशणा करने की कोि ा ा की है, किसी प्रकार के आंकडे देने की कोि ा ा नहीं की गई। जब में इन पैरों को पढ रही थी तो मुझे अपने स्कूल के समय की एक घटना याद आ गई । जब हम इतिहास पढा करते थे तो उसमें राजा–महाराजाओं के द्वारा किये गये कार्यो का लेखा जोखा होता था। सम्राट अ ाोक के काल से लेकर मुगल बाद ााहों के समय

तक हम यह ीपढते आये कि फलां राजा ने कुयें खुदवाये, इतने पेड लगवाये, तालाब बनवाए आदि आदि। इम्तिहान में यदि ऐसे राजाओं के बारें में प्रश्न आ जाता था जिनके बारे में हमने पढ़ा नहीं होता था तो भी उसके उत्तर में हम लिख देते थे कुयें खुदवाये गये, पेड़ लगवाए गए और तालाब बनवाए गये, क्योंकि हम यह समझते थे कि ये काम तो किये ही होगें। (हंसी)उपाध्यक्ष महोदय,काम तो वही होते हे जो पहलेहुआ करते थे । क्योंकि अच्छे काम हर राज में होते है। लेकिन अगर सरकार रोटीन स्टैटमेंट की बजाये यह लिखती कि चालू वर्श में 100 डिस्पैंसरियां बनी, 10 बड़े हस्पताल बने, इतनी लम्बी–चौड़ी सड़कें बनी और फलां फलां सड़क का निर्माण किया गया यानि अगर इनके कार्यो को आंकडाबद्ध किया जाता तो विपक्ष की आलोचना से तो हम बच ही सकते थे लेकिन साथ ही अपनी पार्टी के सदस्यों के लिये भी प्रचार की सामग्री जुटा सकते थे। (व्यवधान) जब आप मंच पर खडे होकर यह कहे कि चालू वित्त वर्श में 100 हस्पताल बनवा दिये हे तो आंकडे आने से इसकी जांच भी हो सकती हे, कोई भी व्यक्ति इन आंकडों की जांच कर सकता है। लेकिन अगर हम राज्यपाल के अभिभाशण में यह कहें कि नई कालोनियां बन रही है, हस्पताल बन रहे है, यह गैर–जिम्मेदारान बयानहै, इसमें कोई वजन नही है। इसलिये मेरा एक सुझाव है कि मंत्री महोदय, अपने–अपने विभाग की उपलब्धियों का पूरा बयौरा आंकडेबद्ध करके भेजें ताकि राज्यपाल के अभिभाशण के लिये सदन में विचार

करने के लिये पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो सके। पैरा 11 में कहा गया है:—

''इस समय सरकार आलुओं की पैदावार बढ़जाने के कारण आलू उगाने वाले किसानों के हितों की रक्षा के लिये यथासम्भव प्रयत्न कर रही है''

क्या प्रयत्न कर रही है, इस बात का कोई जिक नहीं हैं अगर सरकार यह लिख देती कि सरकार आलूओं को खरीदना चाहती है या सरकार ने आलूओं का मूल्य नि चत कर दिया कि इससे कम भाव पर आलू नहीं बिकेगें, आलू का मूल्य गिरने नहीं देगें, ऐसा लिखा होता तो यह तकरीर अच्छी होती ओर सदन के सदस्यों को तसल्ली हो जाती। विधायकों को यह पता लग जाता कि सरकार आलूओं का भाव नि चत करने के लिये फलां फलां काम कर रही है। इसी तरह पैरा 37 पर पब्लिक डिस्ट्रिब्यू ान की बात कही गई। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, भाई खुर ाीद अहमद ने जो बातें कही है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहती, जोउनसे छूट गई है, उनके बारे में कहना चाहती हूं। पैरा 37 में लिखा है—

''ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई के लिये आर्थिक विकास के फल का पूरा वितरण करना पडेगाइसलिये जरूरी चीजों की पब्लिक में में बांट का ढंग वि ोश महत्व रखता हैं सहकारी स्टोर और दूसरी सहकारी समितियां बाजार में मूल्यों को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण काम कर रही हैं''

उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर पर चीजों के मूल्य बढ जाते है, दालों के मूल्य बढ़ जाते है, इस मूल्य को रोकने के लिये सुपर बाजार की चालू कार्य–प्रणाली में समुचित परिवर्तन करके, अच्छा प्रबन्ध करके सुधाार कर सकते है, कोआप्रेटिव मिनिस्टर इस समय हाउस मे बैठे नहीं है...............

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, में निवेदन करना चाहती हूं कि सुपर बाजार की कार्यप्रणाली को इस तरह से बदला जाए कि इस में केवल वही चीजें लोगों को उपलब्ध हो जिनका बाजार में अभाव हो या जिनकी कीमत बाजार में जयादा हो। पब्लिक डिस्ट्रिब्यू ान में इन दोना संस्ााओं का काफी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। जब मौसम की चीजें बाजार में आंए, सरकार उनको खरीद ले और कमी के समय या ज्यादा मंहगाई के समय इनको बेचे। सुपर बाजार ओर सहकारी स्टोरों मे केवल ऐसा ही माल मिले जिसका आम बाजार में अभाव हो या मुल्य ज्यादा हो। अगर सरकार को सबसिडी भी देनी पडे तो सबसिडी भी दे। कालगेट में या हमाम की टिक्की में 5 पैसे कम कर देना कोई योगदान नहीं है। जो व्यक्ति हमाम की टिक्की बाजार से 1रू0 20 पैसे में खरीद सकता है वह 1 रू0 25 पैसे में भी खरीद सकता है। मैं तो यह भी कहूंगी कि मोबाइल वैनज का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिये। जब बाजार में चीजों का मुल्य बहुत बढ जाये तो मोबाइल वैनज एक–एक भाहर और एक–एक गांव में जाये। आप देखते हे कि

कई बार दालों का भाव बढ जाता है , डालडा मंहगा हो जाता है, मिट्टी के तेल का अभाव हो जाता है और कीमतें बढ जाती है। ऐसे समय में मोबाइल वैनज जगह–जगह पर जाकर सस्ते भाव पर लोगों को ऐसी चीजें सप्लाई कर सकती है और पब्लिक डिस्ट्रिब्यु ान के इस सिस्टम को हम आधुनिक बना सकते है ।तो मेरा सुझाव है कि इन दोनों संस्थाओं की कार्यप्रणाली में आमूल–यूल परिवर्तन करके इसको आधुनिक संदर्भ के अनुरूप बनाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, पैरा 7 में बिजली की सप्लाई के बारे में कहा गया हैं इसकी सप्लाई के बारे में यहां जो आंकडे रखे गये हे ये बिल्कुल सतय है क्योंकि आज गांव–गांव मे किसान कहता है कि पहली बार ऐसा हआ है जो पूरी बिजली मिलने लगी है और कोई कटौती नहीं होती। मैं इसके लिये बिजली ओर सिंचाई मंत्री को बधाइ देना चाहूंगी। (विघन) गांव में बिजली की सप्लाई की स्थिति बहुत संतोशजनक है लेकिन इसके विपरीत भाहरों में स्थिति अच्छी नहीं है। मैने एक दो बार मंत्री जी से यह बात कही भी हैं इसके बारे मे मेरा एक सुझाव है कि बिना बताये बिजली न काटी जाये। यह मैं मानती हूं कि जब तक पूरी बिजली मिलने का प्रबन्ध न हो जाये तब तक बिजली में कटोती तो लगेगी ही लेकिनसुझाव इतना है कि यह जो कटौती है भाहरों में बिजली की इसका समय नि चत कर दिया जायें अगर आप यह कहते है कि सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिजली नहीं देनी है तो मत

दीजिये , पांच घंटे बिजली काट लें, कोई ऐतराज नहीं क्योकि लोगों को मालूम होगा कि पांच घन्टे बिजली नहीं आयेगी। आज क्या होता है? जिन्होने छोटे–छोटे उद्योग धन्धे लगाये हे वे मजदूरों को बुला लेते है लेकिन बिजली अचानक चले जाने के बाद वे खाली बैठे रहते है। जब बिजली आती है तो उनके जाने का समय हो जाता है। मैं अम्बाला की ही बात आपको बता देती हूं हर पांच मिनट के बाद वहां 10 मिनट के लिये बिजली चली जाती हैं बिजली में यह जो आंख मिचौली काखेल चलता है इसमें बडी कोफत होती हैं(विध्न) आप बिजली काटें मगर समय नि ित करके, चाहे उसके लिये आप मुनादी करा दीजिये क्यौकि आपकी सीमांये मैं जानती हूं। जब तक पौंग, डहर, पानीपत और यमुनानगर आदि बिजली घरों से हमें पूरी बिजली नहीं मिलती तब तकहमारे यहां बिजली की कमी रहेगी ही।

उपाध्यक्ष महोदय, एकबात मैं थीं बांध और सतलुज यमुना लिंक के बारे मे कहना चाहूंगी। सतलूज यमुना लिंक का मसला अहम मसला हैं जितने भी अधिवेशन हुये है उनमें यह मसला किसी न किसी रूप में हमारे सामने आया है। कभी इसके बारे में ध्यान आकर्शण प्रस्ताव आया है, कभी आधे घंटे की चर्चा मांगी गई ओर कल भी भाई भाम ोर सिंह जी ने एक प्रस्ताव हाउस के सामने रखा । इससे लाखों लोगो का भाग्य जुडा हुआ है। क्योंकि हरियाणा प्रान्त मूलतः कृशि प्रधान राजय है हमारी आर्थिक इकाई का आधार कृशि है। हम कृशि में तब तक तरक्की

नहीं कर सकते जब तक पूर्णतः सिंचाइ न हो। इसके वगैर हमारा उत्पादन बढ़ नहीं सकता। अगले वर्श की योजना में पजाब के इलाके में सतलुज–यमुना लिंक स्कीम पर खर्च करने के लिये 16 करोड़ रूपये रखे गये हैं काम की गति को देखते हुये इस खर्च को जरूरत के मुताबिक बढा देने की बात भी इसमें लिखी हुई है। आप इस रा ि ा को कितना भी बढा सकते है। मैं हाउस की तरफ से आपको यह आ वासन दिलाती हूं क्योकि मुझे वि वास है कि इस खर्च के बारे मे ंसदन के किसी भी सदस्य को आपत्ति नहीं होगी क्योकि ये सब चाहते हे कि सतलूज यमुना लिंक जल्दी से जल्दी बनना चाहिये। इसमें सबसे गमीार बात यह है कि यह पानी व्यर्थ जा रहा है। इसका किसी को लाभ नहीं हो रहा है। यह न हमको मिल रहा है ओर न पंजाब वालों को मिल रहा है।

थीं बांध के बारे मे भी मैं थोडा सा निवेदन करना चाहूंगी। पिछले दिनों तो यह समस्या बड़ा कुटिल रूप धारण कर चुकी थी क्योंकि बाकी तीन मुख्य मंत्रियों ने फैसला कर लिया थाकि इसमें हरियाणा का हिस्सा नहीं। खैर, बाद में हमारी सरकार के इन्टरवीन करने क`प चात इसमें तरमीम आई और इसकी लेटैस्ट स्थिति यह है कि प्रधान मंत्री ने इस मामाले को अटौर्नी जनरल को रैफर कर दिया ह।। लेकिन मैं चौधरी वीरेन्द्र सिंह और मुख्य मंत्री जी से यह गुजारि ा करना चाहूंगी कि अटौर्नी जनरल बड़े लीगल और टैक्नीकल माइन्ड के होते है। उनके सामने हम सिर्फ यही बात न रखे कि नैतिक पहलू में से इसमें

हमारा हिस्सा बनता हैं बल्कि यह भी कहें कि राज्य पुनगर्ठन अधिनियम के अनुसार भी हमारा हिस्सा बनता है। यह हमारा जायज हक है । इसको पंजाब के पिछले मुख्य मंत्री ने माना भी है। मुझे तो हैरानी है कि पंजाब के वर्तमान मुख्य मंत्री, श्री प्रका ा सिंह बादल, एक और तो हरियाणा के साथ हमदर्दी रखते है और दोस्ती की बात करते है लेकिन दूसरी तरफ जब हमारें किसी अधिकार की बात आती है तो अड़ जाते हैं मुझे वि वास हैकि राव साहब गिला नहीं करेगें यदि मैं ट्रैजरी बैंचिज की तरफ से ही नहीं बल्कि सारी अपेाजि ान की तरफ से भी सरकार को यह आ वासन दे दूं कि इस मामला में सारा सदन और तमाम हरियाणा के गेर सरकारी लोग सरकार के साथ है औरहमें हर हालत में आपने हस अधिकार को लेना हैं (विरोधी पक्ष से हां की आवाजें) तो मेरा सरकार को यह सुझाव है कि हम इसे केवल मौरल पाहलू ही न रखें बल्कि बढ़िया से बढ़िया लीगल ऐडवाइस इसके बारे मे ले और अच्छे से अच्छा कानूनी सलाहकार इसके लिये ऐनगेज करै चाहे कितना ही पैसा हमें खर्च करना पड़े क्योंकि जो हक हरियाणा का है वह हम लेकर रहेगें। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मुझे पैरा 19 के बारे में भी कहनी है। इसमें लिखा है कि राज्य सरकार गेर सरकारी कालेजों की माली हालत के प्रति चिंतित है और सरकार ने फैसला कियाहै कि इन कालेजों कै 75 प्रति ात घाटे को पूरा किया जाये जबकि पिछले वर्श 30 प्रति ात घाअे को पूरा कियागयाागि। अन्य आर्थिक

सहायता को मिला कर गेर सरकारी कालेजों के कुल 84 प्रति ात घाटे को पूरा किया जा रहा है। ये आंकडे उपर से तो सराहनीय लगते है लेकिन यदि गहराई से देखा जाये तो असलियत समने आ जाती हैं 84 प्रति ात घाटा सरकार द्वारा पूरा करने की घोशणा करने पर भी कितने कालेजों की माली हालत खराब चल रही है। लेकिन समझ में नहीं आता कि आज भी सरकार कोई दूसरा कदम नहीं उठा रही है। आपको मालूम होगा कि विधायक होस्टल के सामने द्रोणाचार्य सनातन धर्म कालेज के ि ाक्षक धरना लगाये हुये है। कोई भी व्यक्ति आसानी से धरने पर आकर नहीं बैठता। आप सुन कर हैरान होगें कि 16 महीने से आर्टस के लैक्चरारज को ओर पिछले 23 महीने से सांयस के लैक्चररज को तनख्वाह नहीं मिली है। टीचर्ज ऐसे लोग नहीं है जिनके पीछे पीछे बडी जमीन जायदाद है। इन अध्यापको का कोइ सैकन्डरी धन्धा भी नहीं है। एक कर्मचारी को अगर एक महीना तनख्वाह न मिले तो उसका बजट बिगड जाता है। अब आप कल्याण कीजिये कि जिस अध्यापक के पिछले 16 महीने से या 23 महीने से तनख्वाह न मिली हो उसका कैसे गुजाराचल रहा होगा? आज उसके बजट की हालत कंहा चली गई होगी? ठीक है हरेक आदमी का रसूख होता है लेकिन कंहा तक? महीना, दोमहीने या तीन महीने तक तो किसी के धर परिवार का कोइ पालन पोशण करें लेकिन सारी उमर का कोई ठेका नहीं लेता। इसलिये आज मैं ि ाक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री जी से यह गुजारि ा करना चाहती हॅं कि ि ाक्षा विभाग में यह जो नीति बनी हुई है कि अगर कोइ टीचर

ि ाकायत कर देता है कि उसके कालेज की मैनेजमैंट उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती या कुछ गड़बड़ कर रही हैं तो आप उस कालेज की ग्रांट बन्द कर देते हेख इसमें परिवर्तन आना चाहिये। यह कहां का इन्साफ हे कि टीचर्ज ि ायकायत ले कर जाते है तो उसके बदले में कालेज की ग्रान्ट बदं कर दी जाती हैं प्रबन्धकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। आप कालेज के प्रबन्धकों को मजबूर करें कि उनका वेतन समय पर दिया जाये। आप इस नीति को बदलें कालेज की ग्रान्ट बन्द नहीं की जानी चाहिये। यह कोई औचित्य नहीं है कि टीचर्ज हड़ताल करें तो कालेज की ग्रन्ट बन्द कर दी जाये। आप कोई ऐसा प्रावधान करे जिससे प्रबन्धको के और मैनेजमैंट के खिलाफ कार्यवाही कीजा सके। आप चाहैं मैंनेजमैंट की प्रोसीक्युय ान रके लेकिन कालेज की ग्रान्ट बन्द नहीं होनी चाहिये।उपाध्यक्ष महोदय, ग्रान्ट बन्द कर देने से उनको कोई फर्क नही पड़ता है लेकिन टीचर्ज को वतन समय पर नही मिलता। अगर सरकार प्रबन्धकों को यह धमकी दे कि तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही की जायेगी तो वे अगले ही दिन ि ाक्षकों को एक–एक पैसा दे देगें। इसलिये आप इस नीति में परिवर्तन कीजिये। यह बिल्कुल नही होना चाहिये कि कालेज की ग्रान्ट बन्द कर दी जाये और ि ाक्षकों को सडक पर खडा कर दियाजाये। द्रोणाचार्य कालेज की समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है। उस कालेज के ि ाक्षक धरना दिये बैठे है ओर उनको कितने ही महीनों का वेतन नहीं मिला है। इसलिये मैं ि ाक्षा मंत्री से गुजारि ा करूंगी कि वे वहां पर स्वयं जायें और

जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझायें। उन्हे आ वासन दे कर उनकी भूखहड़ताल को समाप्त करवायें।

उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है। मेरे दूसरे साथियों ने भी बोलना है। इसलिये सरकार के समने जो मैंने सुझाव रखे है उनकी और सरकार ध्यान दे। मैं इस बात की सरकार की प्र ांसा किये बगैर नहीं रह सकती कि सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिये जो राहत कार्य किया है वह आज से पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। बाढ़ कुछ तो प्रकृति की देन है, वह किसी के बस की बात नहीं है लेकिन जब से जनता सरकार बनी है तभी से दोनेा सालों में बाढ़ आयी हैं। बाढ़ कोई पहली ही बार हरियाणा में नही आयी है, तीस वर्शो से आ रही हे लेकिन जनता सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिये जो राहत कार्य कियाइतना पहले कभी नहीं किया गया। वैसे तो सारे राज्य के लिये सरकार ने स्कीमें बनायी है परन्तु कुछ क्षेत्र ऐसे है जहां पर बहुत ही अधिक मात्रा में बाढ़ आई है वहां वि ोश प्रबन्ध किये गये है। इस कार्य के लिये मैं सरकार को बधाई देती हूं।

एक बात मैं अपने हल्के के विशय में कहना चाहती हूं और मैंने पिछली बार भी इस मसले को यहां हाउस में उठाया था। जहां तक तीन सौ रूपये देने की बात थी वे तो मेरे क्षेत्र में बांट दिये गये है, परन्तु जो किरायेदारों को ग्रांट देने की बात है वह अभी तक नहीं मिली है। केवल 75 हजार रूपया बनता है। यह पैसा अभी तक बकाया पडा हुआ है। रैवेन्यू मिनिस्टर साहब भी आ

गये हैं राठी साहब से मैने इस बारे में बात की थी ओर वे मान भी गये थे। इस ग्रान्ट को भी सरकार जल्दी से बंटवा दे तो बडी कृपा होगी क्योकि यह ग्रान्ट 31 मार्च तक ही बांटी जा सकती है। मैं राठी साहब से निवेदन करूंगी कि वे जल्दी से जल्दी इसको बंटवायें ताकि उन गरीब लोगों की सहायता हो सके। अम्बाला छावनी के लोग भी इस इन्तजार में है कि जनता सरकार जहां अन्य क्षेत्रों के लिये इतना कुछ भी कर रही है। हमारी और भी ध्यान देगी। इन भाब्दों के साथ मैं इस प्रसताव का समर्थन करते हुये अपना स्थान लेती हूं।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

"That an Address be presented to the governor in the following terms-

'That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Sesison are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 28th Februray, 1979."

I have received notice of an amendment to this motion. It will be deemed to have been read and moved.

1-	**Rao Birender Singh**	
2	**Sh. Shamsher Singh Surjewala**	
3.	**Rao Dalip Singh**	That in the motion, the

4.	**Sh. Surender Singh**	following be added at the end, namely.
5.	**Sh. Jagjeet Singh Pohloo**	
6.	**Sh. Narain Singh**	
7.	**Sh. Inderjeet Singh**	
8.	**Sh. Mange Ram Gupta**	

(1) but regret that it has failed to mention the deteriorating Law and Order situation in theState resulting in sharp increase in the incidents of murders, dacoities, thefts highway robberies, rape etc.

(2) but regret that it does not contain any proposal for solving the ever increasing umemployment among the educated unemployed in the State and failed to provide the uemployment allowance,

(3) but regret that there is no mention of the serious unrest mongst the students in the universities,

(4) but regret that there is no mention of relief to the Traders in the matter of Salex Tax. Market Fee and to remove the rigours of Food Adulteration Act.

(5) but regret that there is no mention regarding the amelioration of the lot of Harijans, including the Safai Karamcharies,

(6) but regret that there is no mention of securing the transfer of control of Canal Head Works situated in Pubjab to the Bhakra Management Board, as decided by the Central Government,

(7) but regret that there is no mention of transfer of Fazilka-Abohar and other Hindi speaking areas, left out in Pubjab to Haryana.

(8) but regret that there is no mentions of atrocities being committed against minority community residing ingurgaon Distt.,

(9) but regret that there is no mention of concrete proposal/steps for securing remunerative prices of agricultural produce,

(10) but regret that there is no mention of the prevailing unrest and large scale retrenchment, lay-offs, lock-outs and repression let loose on theindustrial workers in the State.

(11) but regret that there is no mention of the large-scale persecutions/harassment, and victimisaiton of the political opponents by the Janata Party Government in the State.

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुये)

राव बीरेन्द्र सिंह(अटेली): माननीय स्पीरक साहब, गवर्नर साहब के अभिभाशण के उपर धन्यवाद का प्रस्ताव हमारे दो माननीय सदस्यो की तरफ से पे ा किया गया हैं । स्पीकर साहब, गवर्नर साहब की जात की हमसब बहुत इज्जत करते है। हमें भी गवर्नर साहब के ओहदे के लिये बड़ी हमदर्दी है लेकिन सरकार उनसे जो कुछ कहलवाना चाहे वह उनको अभिभाशण में कहना

पड़ता है। असलियत इस ऐड्रैस में क्या है, इसका काफी चर्चा बहिन सुशमा जी ने ओर मेरे दोस्त चौधरी खुर ाीद अहमद जी ने कर दिया है ंचन्द बातों की तरफ मैं भी सरकार काध्यान दिलाना चाहता हूं । बहुत जोर से एक बात इस ऐड्रैस में सरकार की तरफ से आई हैं सरकार ने इस ऐड्रैस में कहा हे कि लोगों की तरक्की के लिये, कलीन ऐडमिनिस्ट्रे ान के लिये नया स्टाइल यह अपनायेगी। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि वे नये स्टाइल क्या होगें जो सरकार ने पहले नहीं अपनाये हैं इस स्टाइल के बारे में सरकार की और से कोई तफसील इस ऐड्रेस में नहीं दी गई है लेकिन एक बात आम देखने में जरूर आ रही है कि सरकार सारे महकमों को किस तरीके से चला रही है ओर किस तरीके से ऐडमिनिस्ट्रे ान को चला रही है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं हैं अब नये तरीके से वह कैसे चलायेगी ओर किस नये ढंग से स्टेट की पोलिटिक्स को चलायेगी, वह आने वले समय में पता लगेगा।

जहां तक ऐडमिनिस्ट्रे ान का ताल्लुक है, इस बारे में मैं यही कहूंगा कि या तो सरकार को अपने अफसरों पर भरोसा नहीं या बार–बार उनका ट्रांसफर करके से यह देखना चाहते है कि कौन सा अफसर कहां कनविनियन्ट हैं ।ऐडमिनिस्ट्रे ान को चलाने के लिये सुटेबिलिटी भीदेखते है।पिछले दिनों में देखने में आया है कि कई जिलों मे तो चार–चार बार डिप्टी कमी नर्ज और एम0पी0 को तब्दील किया गया। यहां सैक्रेटेरियट में हैड

आफ दी डिपार्टमेंट को भी चेंज किया गया और सब से ज्यादा ध्यान तो सरका का ऐजुके ान के डी0पी0आई0 की तरफ रहा है जिसको बार–बार चेंज किया जाता हैं

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): मेरे विचार में तो भुरू से ही भारद्वाज जी डी0पी0आई0 चले आ रहे हैं । (विघन)

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, सिविल लिबर्टी और ला एंड आर्डर के कन्ट्रोल में रखने का भी सरकारकी तरफ से जिक हुआ । सरकार नें कहा है कि वित्त ला एंड आर्डर कन्ट्रोल में है। सरकार का यही मकसद है कि वे हमें यह बताना चाहते है कि अपोजी ान के एम0एल0ए0 अपने घर स ेचल कर यहां ठीक तरह से पहुचं जाते है तो ला एडं ऐडमिनिस्ट्रे ान ठीक चल रहा है लेकिन किस तरीके से लूट–पाट और धोखाधड़ी हो रही है, यह किसी से छिपी नहीं है। पिछले एक साल के अन्दर हरियाणा में 247 मर्डर हुये । इसके मुकाबले में उससे पहले पीरियड में, यानि जनता सरकार के आने से पहले 147 मर्डर्ज की क ुल तादाद थी। मर्डर्ज की तादाद लगभग डबल हो जाना यहां की ला एंड आर्डर सिचुऐ ान को बताता है।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): बाकी गोली से मारे जातेथ थे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः केस रजिस्टर नहीं होते थे।

राव बीरेन्द्र सिंहः सरकार के पास यह कहने के सिवाये और है ही क्या कि केस रजिस्टर नहीं होते थे।

श्री दीपचन्द भाटियाः आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। मै आपके द्वारा राव साहब को यह बतानाचाहता हूं कि पिछली सरकार के वक्त ऐसे सैकडों केसिज होते थे कि मर्डर हो जाते थे, लेकिन वे रजिस्अर नहीं किये जाते थे।

श्री अध्यक्षः यह कोई पवांयट आफ आर्डर नही ंहै। भाटिया साहब, आप बैठ जाइये।

राव बीरेन्द्र सिंहः इसी तरीके से डकैतियों की संख्या बढी है। लोगों को सिविल लिबर्टीज कैसे ज्यादा मिली है, यह तो सिर्फ एक चीज में जाहिर हो जायेगा कि पिछले एक साल में जनता सरकार के राज में 107/151 के तहत 26000 लोगों को गिरफतार करके जेलों में डाला गयाहै। (व्यवधान)

एक आवाजः हो सकता है 26000 सत्याग्रही गिरफतार किये गये है।

चौधरी संत कवरः 26000 तो इन सब को वोट भी नहीं मिले है।

राव बीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, जहां तक सत्याग्रहियों का ताल्लूक है, आज उनके खिलाफ भी सबसटैंटिव औफेन्सिज के मुकदमें दर्ज हो रहे है और अदालत में वे बेचारे मुकदमें भुगत रहे

है। आप सत्याग्रही को सत्याग्रही को सत्याग्रही तो मानते ही नहीं हो। हम ने सत्याग्रह किया लेकिन आपने झूठे मुकद्मे बनाये है।.... .....(व्यवधान) एक नया स्टाइल अब आपकी सरकार ने अपनाया हुआ है ओर वह नया स्टाइल अच्छा चल रहा है। वह नया स्टाइल क्या है? पोलिटीकल फायदा उठाने के लिये ज्यादा से ज्यादा इंस्टीच्यु ान्ज का स्टेट अन्डरटेकिंग्ज का और कारपारे ान्ज इत्यादि का इस्तेमाल किया जाये। मेरे दोस्त चौधरी देवी लाल सन 1967 में सलाह दिया करते थे कि जितने भी एम0एल0ए0 नाराज होते है, उन सब को कोई न कोई कारर्पोरे ान वगैरा का चेयरमैन बनाकर तनख्वाह क्यों नही दिला देते तब मैने इनकी सलाह नहीं मानी थी लेकिन आज इनको मोका मिला है, आज वे अपनी उस पालिसी को लागू कर रहे है।

Mr. Speaker: Rao Sahib, history is repeating itself. Is it?

राव बीरेन्द्र सिंहः यह हिस्टरी हमने तो नही बनायी। यह हिस्टरी तो किसी और ने बनायी ओर वे सब तो उसके माध्यम बन गये। जिस तरीके सेयहां पर औथटेकिंग सैरीमनीज हुई है और आज वजीर कितने हो गये है, यह गिनने में भी नहीं आते कि 16 है या 17 है।

डाक्टर मंगलसैनः गिनती नही आती। गिनती नहीं आती तो एक आध मुनीम रख लो।

राव बीरेन्द्र सिंहः मुनीम तो रख भी लूं लेकिन मुनीम कसाई का काम तो नहीं कर सकता। स्पीकर साहबख जिस तरीके से इनडयुसमैंटस दी गयी है, पब्लिक लाईफ को खराब करने के लिये यह बडी अफसोसनाक चीज है। मैं अर्ज करूंगा बगैर नाम लिये कि दर्जन एम0एल0एज0 तो ऐसे है जिनको कोआप्रेटिव डिपार्टमेंस खास तौर पर वीकर सैक ान्ज की सेवा करने के लिये लगा हुआ है। तो मेरा ख्याल यह है कि अगर आज कोई सबसे ज्यादा वीकर सैक ान इनको नजर आता है तो वह हरियाणा के एम0एल0एज0 ही है।

Chaudhri Khurshid Ahmed: Mr. Speaker, sir, on a point of order. This is an asersion on all the members that they are the eakest section of the society. I object to it and I request that these words may be expunged.

राव बीरेन्द्र सिंहः वीकर सैक ान कौन सा है, यह तो आप जानते है लेकिन मैंने तो अन्दाजा लगाया है। मैं गलत भी हो सकता हूं। सरकार की तरफ से इंस्ट्रक ांज इ ाु हुई चीफ सैक्रेटरी साहब की तरफ से यह इंस्ट्रक ान्ज की एक चिट्ठी गयी है जो 21–12–1978 की है। इस में यह हिदायत दी गयी है कि जो नान–आफी ीयल मेंबर्ज और एम.एल.ए. चेयरमैन कोआप्रेटिव बैंक्स के या दूसरे इंस्टीचयू ान्ज के बनाये गये है, उनको एक हजार रूपया महीना तनख्वाह और एक हजार रूपया महीने का एक फर्नी ाड हाउस दिया जायेगा। अगर ऐसे मकान नहं है तो 800 रूपया उनको अलाउन्स दिया जायेगा। इस तरह से 2 हजार रूपया

महीना तो एक और 51 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से डी0ए0 और टैलीफौन और ट्रैवलिंग अलाउनस भी इन्हे मिलेगा। 12 एम0एल0एज0 तो ऐसे है जो इन बैंक्स के चेयरमैन बना दिये गये है हो सकता है मेरी गिनती में कुछ न आये हो। लेकिन मैं तो इतने ही गिन पाया हूं।

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): आपके वक्त में कितने थे?

राव बीरेन्द्र सिंहः यह तो आप मेरे फाइनैंस मिनिस्टर से पूछो। आपकी पार्टी ने तो 10 फीसदी वजीर रखने की बात की थी लेकिन हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। हमने तो जनसंघ को भी बाहर रखा था। आपकों याद होगा आपने मुझ पर यह इल्जाम लगाया था कि मेरा एस0वी0डी0 मिनिस्टरी जनसंघ के बूते चल रही है इसलिये मैं छोडता हूं। आपका यह ब्यान अखबारों में भा भााया हुआ था। आपने अपनी मिन्स्टिरी में 4 सीटें जनसंघ को दे रखी है।

डा0 मंगल सैनः यहां कोई जनंसघ नहीं है सारे जनता पार्टी के है? (व्यवधान एवं भाोर)

Local Government Minsiter¼Chaudhri Ram Lal Wadhwa): There is no Jan Sangh now. It is Janata Party.

राव बीरेन्द्र सिंहः यह बात तो आपकी यू0पी0 में साबित हो गयी है। डाक्टर मंगल सैन जी, जरा इन्तजार कीजिये, आपका भी नम्बर आ जायेगा।

डाक्टर मंगल सैनः इन्तजार है जी। आपका नम्बर इधर नहीं आता।

राव बीरेन्द्र सिंहः इसके अलाव 15 एम0एल0एज0 ऐसे है जिनका स्टैट कारपोरे ान का चेयरमैन बनाया गया है।

चौधरी गंगा रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मैं राव साहब को यह बताना चाहता हूं क्योकि इन्होने कोआप्रेटिव बैंको के चेयरमैनों की बात की है कि सारे कोआप्रेटिव बैंको के चेयरमेनों को बने हुये किसी को 8 महीने, किसी को 9 महीने और किसी को 6 महीने हो गये है लेकिन आज तक यह रिकार्ड है कि किसी भी चेयरमैन ने कोआप्रेटिव बैंक से कोई टी0ए0डी0ए0 या कोई तनख्वाह नहीं ली है। अगर किसी के खिलाफ कोई बात हो, तो यह साबित करके दिखा दें।

Mr. Speaker: Please sit down. This is no point of order. I would request the hon. Members not to interrupt the proceedings like this.

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं तो किसी एक ऐसे एम0एल0ए0 को जानता नहीं जो चेयरमैन बना हो, ओर पढा लिखा कोई खास ज्यादा हो। यहां पर तो ऐसे–ऐसे लोग बैठे है जो

मिडल पास भी नहीं है और यह उम्मीद करते है कि वे चेयरमैन बन जायेगें और कुछ व्यक्ति ऐसे है जो बने भी हुये है।

चौधी गंगा रामः आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, मैं राव साहब को यह बताना चाहता हूं कि कोआप्रेटिव बैंकों के चेयरमैंन एम0ए0एल0एल0बी0 भी है आपतो केवल मिडल पास की बात करते हो। ऐसे–ऐसे जिन्होने 10 साल तक कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जेलें काटी, मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि हमने जितनी कुर्बानियां की है, आप तो अगले जन्म में भी उतनी नहीं कर सकते। (व्यवधान व भाोर)

राव बीरेन्द्र सिंहः यह ज्यादा जानते है लेकिन मैं भी कुछ जानता हूं। यह बतायें कि हिसार और जींद में जो चेयरमैन लगाये हुये है वे कितना पढे हूये है। इसी तरह से पन्द्रह एम0एल0एज0 को तो स्टेट कार्पोरे ंज का चेयरमैन बना दिया गया हे ओर अभी कुछ और बनने है जिनका नाम चल रहा है ंस्पीकर साहब, पोलिटिक्स के 27 आदमियों को इस तरह से ऐकमोडेट करना बडी आ चर्य की बात हे ओर में समझता हूं कि इसमें जयादा भद्दी कोई बात नहीं हो सकती।

चौधरी देवी लालः पोलिटिकल नुमाइन्दों के उपर जिम्मेदारी डाली गई हैं।

राव बीरेन्द्र सिंहः फिर गवर्नर साहब के ऐड्रस में कहा गया है कि डिवैल्पमेंट स्कीम्ज की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया

गया है। वे डिवैलपमेंट स्कीम्ज किसान के लिये हैं किसान का ऐग्रीकल्चर के साथ सीधा सम्बनध है। अगर ऐग्रीकल्चर ठीक नहीं है तो इंडस्टरी भी ठीक नहीं है, दुकानदारी भी ठीक नहीं है ंहर चीज की डिवैलपमेंन्ट ऐग्रीकलचर की डिवैलपमेंट पर निर्भर करती हे और ऐग्रीकल्चर की डिवैलपमेंट पानी और बिजली पर निर्भर करती है।पानी के लिये अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो एग्रीक्लचर को क्या डिवैलप करेगें? सतलूज यमुना लिंक को आज तक अप खुदवाने मे नाकायाब रहे है । आप जनता को झांसा देते रहे कि हमारी दोस्ती है हमस ब कुछ करेंगें। छोटी सी बात थी कि सैन्टर की हकूमत ने यह फैसला किया कि पंजाब में जितने भी हैडवर्क्स बाकी है वे भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को सौंप दिये जायें। लेकिन आप इनहैड सर्क्स को भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को नहीं दिलासके और आज हरियाणा का किसान रोता है कि हमें पानी का फेयर भोयर नहीं मिल रहा है। कल इसी हाउस में मिनिस्टर महोदय पने फरमाया कि कैनाल से पानी मिले या न मिले लेकिन आबियाना जरूर देना पडेगा क्योकि उसकी जमीन नहरी लिखी हुई है। आप इस तरह से किसान की मदद कर रहे है। सुशमा जी कह रही थी कि हरियाणा में सिकान को पूरी इलैक्ट्रिसिटी मिल रही है। स्पीकर साहब, अगर इलैक्टिरीसिटी पर पूरा भरोसा कर लिया जाता तो सारी फसल ही तबाह हो जाती। आपकी बिजली की तेा हालत यह रही है कि कभी रात को बिजलती मिल रही है कभी दिन में थोडी देर के लिये बिजली दी जा रही है । यह तो भगवान ने मदद कर दी जिससे कुछ फसल हो गई वरना आपकी

बिजली के भरोसे अगर किसन रहते तो बेचारों की फसल ही तबाह हो जाती ओर जैन साहब का खजाना धरा रह जाता। (व्यवधान) मैं तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप सब से मेरी बात सुनें। स्पीकर साहब, किसान को अगर उसको पैदावार का सही भाव दिला दिया जाये तो सारी दिक्कतें दूर हो जाए। आज सरकार ने एक बहुत भारी बात कही कि हम अनाज की 58 लाख टन पैदावार ले जाना चाहते है। स्पीकर साहब, 1966–67 के अन्दर हरियाणा मे अनाज की पैदावार 21 लाख टन थी और यह रिकार्ड है कि सन 1967–68 में एस0वी0डी0 गतर्नमेंट के चन्द दिन के राज के बाद यह पैदावार 21 लाख टन से बढकर 42 टन लाख टन हो गई और आज बारह साल के बाद 42 लाख टन से 58 लाख टन तक ले जाने की कोि ा ा कर रहे है। यह पैदावार इसलिये नही बढेगी कि आपका किसान की पैदावार का उचित पैसा दिलाने की तरफ ध्यान नहीं है। स्पीकर साहब, आज आप देखे कि आलू का क्या भाव है? लेकिन चौधरी खुर ाीद अहमद चाहते है कि उनका साठ मील का इलाका नेश ानल वैजीटेबल रीजन के लिय सुरक्षित कर दिया जाए। स्पीकरसाहब, 45 रूपया फी क्विंटल आलू के उपर खर्चा आता है और बाजार मं आलू का भाव पन्द्रह रूपया क्विटल है (व्यवधान)। आम किसान को तो पन्द्रह रूपया क्विंटल का ही भाव मिल रहा हैं इसी तरह से गन्ने को कोइ पूछ नहीं रहा है , आलू को कोई नहीं पूछ रहा है। पिदले साल सरसों का भाव 400 या 450 रूपये क्विटल था लेकिन आज कोई दो सौ रूपया में भी नहीं पूछ रहा है। कपास का भाव दो सौ रूपया क्विटल हो गया

है। जब दो सौ रूपया क्विंटल कपास बिक रही है तो किसान क्या कमायेगा और क्या खायेगा। उसके बाद बात यह हो रही है कि ाकेआप्रेटिव से कर्जा दे देगें हरिजनो के लिये चौपालें बना देगें और पानी दे देगें। चौधरी साहब गवर्नर ऐड्रेस में इन चीजों को पढने से हरियाणा की जनता आपकी सरकार को अच्छा नही समझती। काम करके दिखाओगे तब कुछ बात बनेगी। ऐड्रस में फलड का जिकर किया गया कि काफी रिलीफ दी गई है, काफी पैसा खर्च यिका गया है इसमें कोई भाक नहीं हैलेकिन इससे लोगों को क्या फायदा पहुंचा है। मै अपने इलाके की बात बताता हूं कि मेरे इलाके में साहबी नदी से सब से ज्यादा नुक्सान होता है। वहां पर मकान की रिपेयर के लिये तीन सौ रूपया दिया गया और यह रूपया किन मकानों के लिये दिया गया जो हंड्रैड परसैन्ट बरबाद हो गये। स्पीकर साहब,अगर एक मकान पूरी तरह से खत्म हो जाए उसके लिये तीन सौ रूपया दिया जाए और वह भी भाक्ल देखकर दिया गया है। पूछ कर दिया गया है कि साहब कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, यह कितने अफसोस की बात हैं। झज्जर तहसील में और रेवाड़ी तहसील में हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो गई ओर दस पन्द्रह साल तक वाहं कोई चीज उगाई नहीं जा सकती लेकिन सरकार ने उस जमीन को ठीक करने के लिये कोई साधन मुहैया नहीं किये और न ही इस बात को माना है कि जो जमीन फ्ल्ड से नाकारा हो गई है उनसको कुछ रिलीफ दी जाये। (चौधरी राम लाल वधवा की तरफ से विघन) चौधरी राम लाल जी आप तो आज सिफारि ा कराकर बच गये है।

(विधन)पावर का फलैट रेट करने का फैसला सरकार ने किया है लेकिन उसमें भी डिसकिमिने ान यिका गया है।

डाक्टर मंगल सैनः स्पीकर साहग,यह चेयर पर ऐसप र्न है और ये भाब्द ऐक्सपंज होने चाहिये। यह जो सिफारि ा वाली बात कही हे यह ठीक नहीं है।

Mr. Speaker: Rao Sahib, if it is implied that any influence was brought on me, I take strong objection to it. I would request you to withdraw it.

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं बिल्कुल विदड्रा करता हूं । मैं तो अपने दोस्त के साथ हमदर्दी रखता हूं। (व्यवधान) पावर के मामले मे फलैट रेट की बात सरकार ने किसान को सुविधा देने के लिये की हैं कदम अच्छा था लेकिन इसमें भी डिसकिमिने ान हो रही है। स्पीकर साहब, नारनौल तहसील, रिवाडी तहसील और महेन्द्रगढ़ तहसील में पानी की सतह एक जैसी नीची है लेकिन महेन्द्रगढ़ तहसील के अन्दर रेट कम है ओर नारनौल तहसील के अन्दर रेट ज्यादा है। तो कम से कम एक इलाके मैं जो इतनी डिसकिमिने ान है, उसको तो रिमूव करवाये। एक–एक मोटर के उपर 400–400 रूपये का फलैट रेट में फर्क है। यह बडी बेइन्साफी है। गवर्नर साहब ने अपने ऐडैरस में कहा है कि सराकर जवाहरलाल नेहरू कैनाल पर काफी पैसा चार्च कर रही है। पतानहीं कि सरकार इस मामले में कहां तक कामयाब हुई है। हमारी कामयाबी तब होगी जब हम सतलुज ब्यास और यमुना

के पानी के बंटवारे को लेकर, हैडवर्क्से के मामले को लेकर, केन्द्र द्वारा दिये गये अवार्ड के मुताबिक फाजिल्का ओर अबोहर के इ ू को लेकर अपने केस को परसू करेगें। सुशमा जी ने ठीक ही कहा था कि चौधरी साहब इन मामलों मे काफी होि ायार है। चौधरी साहब इ ू बनाने और पकडने में बड़े माहिर है । मैं इनको बडी देर से जानता हूं कि ये क्या–क्या इ ू उठाकर लड़ते रहे है लेकिन हैरानगी की बात यह है कि यह इ ू उनकी नजर में क्यो नही आया। इससे बडा इ ू तो हरियाणा के लिये और क्या हो सकता है जिससे हरियाणा के लोगों की जिन्दगी बावस्ता हैं अगर सरकार इस मामले पर लड़ना चाहती है तो हम सभी उनके साथ है लेकिन अफसोस की बात यह है कि चौधरी साहब ने हमारी इन माामलो में कही पर जरूरत ही नहीं समझी। यही कहते रहे कि मैं पंजाब वालों से अपनी दोस्ती के नाते सारे काम करवा लूंगा। हमें यह समझ नहीं आ रही कि आखिर यह दोस्ती कब तक चलेगी। पंजाब वालों की तरफ से तो है नही, आपकी तरफ से हीचल रही है। चौधरी साहब, आप जब कुछ करके दिखलाऐगें तभी हम मानेंगें कि आप हरियाणा के लिये कुछ कर रहे है।

स्पीकर साहब, इससे आगे थीं डैम का मसला भी है।

Mr. Speaker: Please conclude your speech, Rao Sahib.

Rao Birender Singh: I have takenonly twenty minutes.

Mr. Speaker: You have taken twenty eight minutes.

राव बीरेन्द्र सिंहः मैं जल्दी ही खत्म करने जा रहा हूं जी।

डाक्टर मंगल सैनः राव साहब, रिवाड़ी के बारे में ही कुछ कह दो।

राव बीरेन्द्र सिंहः डाक्टर साहब, रिवाडी की बात का आपके सामने कहने का क्या फायदा? रिवाड़ी की बात तो हाई कोर्ट सुन रही हैं इस वक्त इसके लिये मैं कुछ नहीं कह सकता। सुशमा जी ने भी कहा है कि आप कालेजों को इम्प्रव करो पर यह नहीं होना चाहिये कि ग्रांटस बंद हो जाये और लैक्चरारज को काफी दे तक तनख्वाहें नह मिले। फिर आपने कालेजो के उपर ऐडमिनिस्ट्रेटर्ज लगा रखे है जो डायरैक्ट डी0सी0 के अन्डर है। हजारो पूलिस मैंन्ज आपके पास कालेजों को घेरने के लिये है , पर मै ंऐसी कोई बात यहां पर नही कहूंगा।

स्पीरक साहब, मै कुछ बातें ला एंड आर्डर के बारे में यहां कहना चाहता हं। आजकल जो डाके पड रहे है उनको देखकर यह मालूम होता है कि लोगों में पूलिस का कोई डर नहीं रहा।हरियाणा में भाायद सात–आठ अफसरों को पुलिस आई0जी0 का रैंक दे रखा है। भाायद ही किसी और सूबें में ऐसा हों लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है कि दिन दहाड़े डाके पड़ रहे है, कत्ल हो रहे है। पिछले दिनों दादरी और महेन्द्रगढ के बीच में 10

ट्रकों को खडा करके डाकुओं ने सारी रात तक लूटा। कनीना में जोकि राव दलीप सिंह जी का हल्का है,उसमें एक गरीब सुनार, उस की बीवी, उसकी दोतीन जवान बेटियों यानि पांच अडल्टस को छुरों से बुरी तरह से घायल कर दिया गया और उनका कुनबा भी बिल्कुल साफ कर दिया। यह जगह थाने से कोई 100 गज मु कल से होगी लेकिन आज तक कोई मुलजिम पकडा नहीं गया।

डा0 मंगल सैनः दो पकडे गये है।

राव बीरेन्द्र सिंहः जो पकड़े गये है वह भी आपकी पलिस की मेहरबानी से नहीं बल्कि उसी मुहल्ले वालों ने ही आइडैंटिफाई किया, किसी को आवाज से पहचाना, किसी को भाकल से पहचाना। इससे आगे मै आपकों बताता हूं कि बावल के हल्के में इसी हफते में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिंटी डिपार्टमेंट के एक एस0डी0ओ0 के घर पर डाका पडा हैं उसके कुनबे को बुरी तरह से मारापीटा गया। तहसील हैडक्वार्टर है, थाना पास ही था पर फिर भी पुलिस आठ घंटे के बाद वहां पर पहुंची। गुड़गांव भाहर के पास एक नाथुपूर गांव है वहां पर भी ऐंसी वारदात हुई और जिस में एक पुलिस मैन को गोली भी लगी। उस जगह से डी0सी0 साहब की कोठी लगभग एक मील पर है, लेकिन अभी तक डाकुओं का कुछ पता नहीं चल रहा कि वे लोग कौन थे। सो इन वारादातों को देखते हुये यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि ला एंड आर्डर कितना नीचे गिर चुका है। इसलिये मैं सरकार से

कहूंगा कि ला एंड आर्डर की बिगडती हुई सिथति को सम्भालने की कोि ा ा की जाये और सरकार को ठीक ढंग से चलाने का प्रयत्न किया जाए।

डा0 मंगल सैनः आपके मि वरे का भाुकिया।

श्री अध्यक्षः राव साहब,आपने काफी समय ले लिया है, अब आप जल्दी खत्म कीजिये।

राव बीरेन्द्र सिंहः मैं जल्दी कर रहा हूं। खुर ाीद साहब की बरादरी के भी काफी लोग हरियाणा मे बसते है। एक सेवली गांव है, वहां पर एक मस्जिद के उपर कब्जा कर लिया गया। एक और मस्जिद है उसके उपर भी कब्जा किया जा रहा है लेकिन सरकार की तरफ से इस मामाले में कोई मदद नरहीं की जा रही हैं ईद के रोज उस मस्जिद को गन्दा कर दिया गया, बाद में साफ कर वाहां पर नमाज अदा की गई। एक कब्रिस्तान का मसला भी है, उसका खसरा नम्बर मैं आपको स्पीकर साहब, दे सकता हूं। उस कब्रिस्तान में ऐक छोटी बच्ची की ला ा दफनाई गई थी लेकिन उस ला ा को उठाकर वहां से बाहर फैंका गया।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि मैं उसी हल्का का रहने वाला हूं जहां की बात राव साहब कर रहे ह। उस गांव में इस प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ। राव साहब बिल्कुल गलत कह रहे है (ाोर).....

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, आप बैठिये। आपको भी बोलने का टाइम दिया जाएगा, आप उस वक्त कह लेना।

राव बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, बजाये इसके कि स्वामी जी बात को मानें, वे उल्टा इन्कार करने के लिये खडे हुये है। खैर, मैं कह रहा था कि ला ा को बाहर निकाल फेंका गया। वहां पर पुलिस पहुंची। डी0सी0 साहब भी मौके पर पहुंचे और यह जो पर्चा मेरे हाथ मे है यह वहां के जिम्मेदार आदमी ने, जोकि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जनरल सैर्कटरी है, ने दिया है । यह मैं आपको देना चाहता हूं ताकि सरकार इस के उपर गौर करे।

Mr. Speaker: You please give it to me in my chamber. I will examine it and admit it if it is a document to be admitted. अब आप अपनी स्पीच वाईंड अप करे।

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं एक दो बातें कह कर खत्म करता हूं। (ाोर)

Sh Surrender singh: He will conclude in 3 to 5 minutes.

Mr. Speaker: He was allotted thirty minutes and, I am afraid, he has already taken thirty-five minutes.

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, एक बात मै ंऔर यहां पर रखना चाहता हूं। पानीपत के अन्दर मुसलमानें की आबादी कोइ तकरीबन 20 हजार की है ंबजाये इसके कि उन लेागों को हाउसिंग के लिये साईट दी जाये ।उन लोगों ने जो वक्फ बोर्ड

की जमीन पर मकान बना रखे है, उस जमीन को भी सरकार अब एक्वायर कर रही है और उन लेागों को वहां से उजाडना चाहती है। इस प्रकार की दरखास्तें जो मेरे पास है यह वहां के काफी बडे मुअजिज लोगों की दी हुई है जो मै ंआपके द्वारा सरकार को देना चाहता हूं ताकि सरकार का ध्यान इस तरफ भी हो। हो सकता है कि इस की एक कापी चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी आई हो, पता नही, उन्होने पढी है कि नहीं है। हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर साहब को इसको पएने का टाईम न मिला हो। कयोकिं चीफ मिनिस्अर साहब बहुत बिजी रहते है। अगर किसी दूसरे सूबें में पालिटिकस चल रही हो तो अपने सूबे की तरफ तो थोडा ही ध्यान दिया जा सकता है। (विघन) स्पीकर साहब, मैं आपको माइनारिटी कम्युनिटीज की बातें बता रहा था–

श्री अध्यक्षः राव साहब आप 35 मिनट से भी ज्यादा ले चुके हेख जब आप कनक्लूड करे।

राव बीरेन्द्र सिंहः मैं ज्यादा वक्त नही लुंगा मैं तो सिर्फ यही अर्ज कंरूंगा कि हरिजनों की तरफ भी सरकारध्यान दे। मै ंआपको एक मिसाल दूंगा कि बिजली बोर्ड के सब–स्टे ंज बनाने के लिये जमीन ऐक्वायर करने की जरूरत पडती है। ठीक है, जमीन लो लेकिन महेन्द्रगढ और गुडगांव में तीन चार केसिज में जाहं जमीन एक्वायर करने जा रहे है वह सारी गरीब हरिजनो की है। उन्होने मु कल से एक आध एकडत्र जमीन खरीदी थी और उसी के उपर सरकार की निगाह पड़ गई । इसलिये मै

कहता हूं कि गरीबों को बख्शों। अगर आपने जमीन लेनी है तो बडे–2 आदमियों की लीजिये। (विघन) इसके बाद मैं एक छोटी सी बात पंचायती राज के बारे मे करूगां । भाुरू–2 में सरकार ने यह वायदा किया था कि जो पंचायते अन–अपोज्ड चुनी जाएंगी उनको हम पांच हजार, तीन हजार और दो हजार रूपये की ग्रंट देगें लेनिक आज तक किसी पंचायत को ऐसी गोन्ट नही ंदी गई है।

चोधरी उदय सिंह दलालः इस काम के लिये 54 लाख रूपया रिलीज कर दिया गया है।

राव बीरेन्द्र सिंहः कर दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब तो यह था कि अगर कोइ वायदा पूरा न किया जाए तो वह अच्छी बात नहीं है। आप हस्पताल ओर सडके बनाने जा रहे है यह बहत अच्छी बात हे लेकिन हस्पताल भी जगह देख कर खोले जाएं यह न हो कि आपके गांव में और मेरे गांव में ही खोल दिये जायें। इसी प्रकार से पीने के पानी की बात हुई है। सरदार लछमन सिंह मेरे पुराने दोस्त है उनसे मुझे उम्मीद हे तो कि वे इन्साफ करेगें लेकिन यह हकीकत है कि जहां पर पहले वाटर सप्लाई स्कीम्ज बन चुकी है उनमें से जो गावं मजून्रे नजर नहीं थे उन गांवों मे`बीच में काम छोड दिया गया और वहां पर पानी नहीं दिया गया।

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह): आप ऐसे गांवों के नाम बताइयै।

राब बीरेन्द्र सिंहः एक गां रेवाड़ी तहसील में काठूवास है। स्कूलों और कालेजों के बराबर से लाइन जा रही है लेकिन आपके महकमें ने यह फैसला कर लिया है कि इंस्टीच्यु ांज को पीने का पानी नहीं देगे।

श्री लछमन सिंहः यह बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नही हो सकता।

राव बीरेन्द्र सिंहः सरदार जी मैं आपको आपके महकमे की चिट्ठी दिखा दूगां।

श्री लछमन सिहंः आप मुझे उसी वक्त मिल लेते, मैं यह बात उसी तक्त ही निपटा देता।

श्री अध्यक्षः राव साहब, अब आप खत्म कीजिये बहुत समय हो चुका है।

राव बीरेन्द्र सिंहः टाइम को देखते हुये मैं इन भाब्दों के साथ आपका भाुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इसके साथ–2 मैं गवर्नर साहब का भी भाुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने यहां आकर अपना अभिभाशण पढा ओर उम्मीद करता हूं कि वे जहां इस सरकार के कारनामों की बात करते ह वहां इसके दूसरे कारनामें पर भी कड़ी निगाह रखेगें।

स्वामी अग्निवे ा(पुंडरी): आदरणीय अध्यक्ष महादेय, राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा के विशय में मैं अपने साथी भाई

खुर ाीद अहमद के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिये खडा हुआ हूं बहिन सुशमा जी ने ठीक ही कहा था कि पहले सरकार का ध्यान जयादा भाहरों की तरफ केन्द्रित होता था लेकिन अ बवह बदला हैं राज्यपाल के अभिभाशण में पहली बार यह दिखाई पड रहा है कि सरकार गांवों की उन्नति के लिये अधिक से अधिक पैसा खर्च करना चाहती है ंजब से जनता सरकार आई है तब से दे ा की हालत बदल रही है और देहात का गौरव जाग रहा है। इसलिये मैं राज्यपाल के अभिभाशण को अगर देहात का अभिभाशण कहूं तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही न्याय संगत होगा। अभी राव साहब ने इस अभिभाशण पर अपनेविचार रखते हये कहा कि गांवों के अन्दर बिजली नही मिल रही है। विरोधी दल के नेता से मै ंउम्मीद करता हूं कि वे अपनी बातें जिम्मेवारी सें रखेगें। जो बात आलोचना के काबिल हो उसकी आलोचना अव य करनी चाहिये और उन्होने खुद भी देखा होगा कि हामर पक्षप की और से भी केवल सरकार की तारीफ ही नहीं की जाती है बल्कि बातों में आलोचना भी की जाती है। इसलिये विरोधी पक्ष के नता से मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात सच्च है उसको सच कहेगें। आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज हरियाणा के अन्दर टयूबवैलों को जो बिजल की सप्लाइ होती हे वह इतनी अच्छी है कि इतनी अच्छी पिछले तीस सालों में कभी भी नहीं रही। (थम्पिंग)। हम भी पहले सोचा करते थे कि जब सरकार कारखानो ं को 18/20 घंटे बिजली दे सकती हे तो किसानो को क्यों नही दे सकती। हमने इस बात के लिये पछली सरकार को

बहुंत कुछ कहा लेकिन उसने हमारी एक बात भी न सुनी। हमने आन्दोलजने भी किये और हमजेलो मे भी रहे लेकिन हमारी बातों को सुना नही गया। आज चौधरी देवी लाल कि सरकार के टाइम में गांवों के किसान जो टयूबवैल्ज चलाते है, उनको लगातार 18–20 घंटे बिजली मिल रही है। जनता सरकार की किसानो को यह एक वि ाश देन है (विघन) तो मैं राव साहब से यह दर्खास्त करूंगा कि अगर वे वास्तविक बातों को स्वीकार करेगें तो उनकी दूसरी बातों मे भी वजन बढ जाएगा। वरना यह सोचा जायेगा कि विरोधी पक्ष के नेता होने के कारण ये विरोध कर रह`है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी खुर ाीद अहमद पदासीन हूये) आदरणीय सभापति जी बिजली मिलने के साथ–2 किसानो को इस सरकार ने एक और बहुत बडी सुविधा दी है वह है बिजली का फलैट रेट करने की। पहले हमारे गरीब किसान बहुत परे ाान रहते थें किसी का अगर मीटर जल जाता था तो उन पर चार्जिज बडे हैवी डाले जाते थे और मीटर के पैसे भी जमा करवाने पडते थे ओर दूसरा मीटर लगवाने के लिये उसे महीनेां दफतरों के चक्कर लगाने पडते थें अब फलैट रेट होने के बाद किसान को किसी गपकार की डिफीक्ल्टी नहीं है।

स्वामी अग्निवे ा: मैं दो चार ओर सुझाव अपनी सरकार के सामने रखना चाहता हूं। कल भी इस पर मैने कहाथा। यह जो सतलूज जमुना लिंक है इसमें जो भी हमारा दावा है वह हमें मिलना चाहिये। इस पर 15 करोड रूपया और चार्च करने के लिये

कहा गया है ंमैं सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पंजाब सरकार कों नहर की खुदाई के काम के लिये रूपया न दिया जाये जब तक वे खुदाई का काम भाुरू न कर दें। (विघन) दूसरी बात मैं फिर यह कहूगा कि यह जो फलैट रेट कर दिया यह बहुत अच्छज्ञ किया लेकिन पंजाब कि अन्दर फलेटरेट साढे तेरह रूपनये प्रति होर्स पावर है जबकि हमारे यहां 18 रूपये है। यह 4–5 रूपये का फर्क क्यो है? वहीं भाखड़ा, वही बिजली है वही खम्बे हैं हरियाणा में वही बिजली आ रही हैं जब पंजाब वाले 13 रूपये मे दे सतकते है तो हम भी 13 रूपये में दे। बे ाक कम से भी दें लेकिन 13 रूपये से ज्यादा के हिसाब से दनेा हमारे लिये उचित नहीं हैं इसके अलावा हमारी सरकार रसायनिक खादोां के प्रयोग का प्रचार करने के लिये ओर फास्फेट और पोटा ा खाद देने के लिये अनुदान दे रही है ंइसके बारे में मेरा एक छोटा सा सुझा वहैं महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि हंमें गोबर की खाद का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहियैं इस दि ाा में उन्होने एक और बडी क्रांतिकारी बात कही थीं उस पर चीन ने तो अमल किया लेकिन हमारे देश में अभी उस पर अमल नहीं हो पायाहै। आज भी हमारे लाखों–करोडो लोगो का जो मल है उसका उपयेग हम नहीं कर पा रहे है वह ऐसे ही नश्ट हो रहा है। यदि इस दि ाा में गम्भीरता के साथ काई कदम उठाया जाये तो इसका बडा लाभ हो सकता हैं गांव–2 में यदि सुन्दर भाौचालय बना दिय जाये ंतो गांव वालो की जो सबसे बडी कठिनाई है, भाौच जाने की ओर खास करके हमारी माताओं बहनों को जो सबसे बडी जिल्लत

भुगतनी पड रही है वह भी दूर होगी और गांव गांव के अन्दर मल इक्टठा करके गोबर गैस भी पैदा किया जा सकता है। और खाद की जितनी समस्याहै, जो हमे रसायनिक खाद विदे ाों से विदे ाी मुद्रा दे कर खरीदनी पड़ रही है, वह समस्या भी हल हो जाएगी। अससे सारे देहात के वातावरण में क्रांति आ सकती हैं।

आदरणीय सभापति जी, अभी गन्ने के बारे मै हमारी सरकार ने कुछ योजनायें घोशित की कि हम 12 करोड़ रूपया सबसिडी देने जा रहे है। कुछ मिल मालिकों को देगे ओर कुद किसानो को देगै जो लोन आप मिल मालिकों को देगे वह यथार्थ में ऐसा लोन है जो आपको वापिस नहीं होगा।सारे हरियायणा में 8 करोड़ टन गन्ने का उत्पादन हुआ। उस 8 करोड़ टन मे से मिलों का जो बौंडिड गन्ना है वह केवल डेढ़ करोड़ टन है ंउस डेढ़ करोड टन गन्न पैदा करने वालो को हमारी सरकार 12 करोड सबसिडी दे रही है ंबाकी के लगभग 7 करोड़ टन गन्ना पैदा करने वालो के लिये हमारे पास कोई योजना नहीं है। इन बेचारो का गन्ना 3 यपये 4 रूपये और ज्यादा से ज्यादा 5 रूपये क्विंटल के हिसब से बिक रहाह है और दूसरी तरफ जो बौंडिड गन्ना है वह 12 रूपये के हिसाब से बिक रहा है। यदि उनको कोई सबसिडी न भी दे तो भी उनका गन्ना 8 रूपये क्विंटल से कम नहीं बिक सकता है। उनकी कीमत तो 8 रूपये क्विंटल ग्रांटिड हैं इसलिये मेरी मख्य मंी जी से, खजाना मंत्री से और कृशि मंत्री से प्रार्थना है कि इस बारे में पुनर्विचार करे। वरना हमें इससे बहुत बडा

नुकसान होने जा रहा है। नुकसान भी एक और किस्म का हेाने जा रहा है। जिनके पास अपनी खेाती नही है वह कही से पर्चियां बना करके 3 रूपये के हिसाब से गन्ना खरीद कर 12 रूपये के हिाब से बेच देता है। यह एक नये किस्म का भ्रश्टाचार है। इसलिये इस भ्रश्टाचार को रोकने के लिये और गरीब किसानों को राहत देने के लिये हमारी सरकार को कोई विचार करना चाहिये।

श्री सभापतिः अब आप वाइंड–अप कीजिये।

स्वामी अग्निवे ाः आदरणीय सभापति जी, पढे देहाती नौजवानों के लिये योजना इस अभिभाशण के अन्दर देखी गई है। मैंने कल भी निवेदन किया था कि पढे लिखें और अनपढ लोगों के बीच में डिसकिमिनेशन न करें। यदि करनी भी हो तो अनपढ़ लोगों की तरफ ज्यादा घ्यान देना चाहिये। हमारे जो पिछड़े वर्ग के भाई है जो हरिजन वर्ग के भाई है, ओरटपरीवास कहे जाने वाले भाई है, उनके बच्चों की पढाई की सुविधा आज नहीं हैं अगर है भी तो बहुत कम है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि गांव के अन्दर जो अनपढ़ लेाग रह गये है, जिन बेचारों की हाली और पाली रोजी है, उनके रोजगार के लिये आपको कोई योजना लागू करनी चाहिये। अभी परसों केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जो बजअ पे ा कियाहै वह एक बहुत ही क्रांतिकारी बजट है। दे ा के अन्दर साबुन, माचिस, कपडा इस प्राकर की जो चीजे है जो कि बडे–बडे मिलों में तैयार हुआ करती थी, उनके उपर उन्होने सैल्ज टेक्स बढ़ाया है, उनके उपर उनहोने

कर बढ़ाये है। इससे क्या होगा? जो लघु उद्योग है उनको बहुत बडी राहत मिलेगी। हमारा बजट भी 4–5 दिन के बाद पे ा होने वाला है। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह हरियाणा को माडर्न स्टेट बना करके दिखायें। यहां हरियाणा में मिलों का बनाया हुआ जुता, साबुन, कपडा आदि न बिकने पाये। इनके उपर भारी कर लगाये जाने चाहिय। गांवों में लगाये जाने वाले लघु उद्योगों की पूरी सहायता की जाए। तभी समसया का समाधान होागं कांग्रेस के भाासन में जो पिछले 32 वर्श से पूंजीपति बढते चले जा रहे हे वह नहीं बढ सकेगें। बिड़ला ने 1947 में अपना बिजनैस 27 करोड़ रूपये से भाुरू किया था ओर कांग्रेस के भाासन में आ करके वह 1100 करोड़ रूपये का मालिक बन गया। यह जो पूंजीपति को पनपाने वाली नीति थी.....

श्री सभापतिः कृपा करके आप वांइड–अप कीजियें।

स्वामी अग्निवे ाः सभापति जी आप मुझे थोड़ा सा समय ओर दीजिये यदि मैं कोई गलत बात कहूं तो आप मुझे रोक दीजिये। जो मैं कह रहा हूं वह मुझे कहने दीजिये।

FINAL (LAST BOOK PAGE MISSING)